सांध्य दैनिक
श्रीकंचनपथ
लीपा पोती नहीं सिर्फ सच
RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्र.-छ.ग./ दुर्ग /94/2023-25

वर्ष- 16 अंक - 52 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरुवार 05 दिसंबर 2024 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

बिलासपुर-रायपुर-कोरबा से गुजरने वाली 9 लोकल ट्रेनें 6 से 9 दिसंबर तक रद्द

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर समेत कोरबा से होकर चलने वाली 9 लोकल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। ट्रेनें 6 से 9 दिसंबर तक नहीं चलेंगी। रायपुर मंडल के हथबंध-तिल्दा नेवरा सेक्शन पर रिलीविंग गर्डर की लॉन्चिंग के चलते रेलवे ने ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है।

रेलवे प्रशासन की ओर से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से पूरा करने का दावा किया जा रहा है। जिसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से होकर चलने वाली ट्रेनों को लगातार कैंसिल किया जा रहा है। रायपुर रेल मंडल में 6 दिसंबर की रात 10 बजे से 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक चार घंटे अप लाइन और 3 घंटे 30 मिनट का मिडिल लाइन में ब्लॉक लेकर काम किया जाएगा। इस दौरान 6 एवं 9 दिसम्बर गाडी संख्या 08719 बिलासपुर-रायपुर मेमू रद्द रहेगी । 6 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08727 बिलासपुर-रायपुर मेमू रद्द रहेगी। 7 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08261 बिलासपुर-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी। 7 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08275 रायपुर-जूनागढ़ रोड पैसेंजर रद्द रहेगी। 8 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08276 जूनागढ़- रायपुर रोड पैसेंजर रद्द रहेगी। 8 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08280 रायपुर-कोरबा पैसेंजर रद्द रहेगी। 9 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08728 रायपुर-बिलासपुर मेमू रद्द रहेगी। 9 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमु रद्द रहेगी। 9 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08733 गेवरा रोड- बिलासपुर मेमु रद्द रहेगी।

कृषि विज्ञान केन्द्र के दो किसानों को मिला मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड

नारायणपुर। कृषि जागरण एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2024 का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रगतिशील कृषकों को प्रोत्साहन करने हेतु सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर के दो प्रगतिशील कृषक ग्राम बांगडोंगरी के चौतू राम यादव एवं बेलगांव के नीलकंठ नाग को मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2024 से 3 दिसंबर को सम्मानित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग से दोनों किसान अपने-अपने परिस्थिति में समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर अपने आय के साधन को बढ़ाया है। चौतू राम यादव खरीफ में धान के साथ देशी मुर्गी पालन करते थे जो वर्तमान में खरीफके साथ रबी सीजन में चना, मटर, मक्का के साथ-साथ मछली पालन, गाय पालन, मुर्गी प्रजनन इकाई एवं केंचुआ खाद उत्पादन कर अपनी आय को बढ़ा रहे हैं और नीलकंठ नाग खरीफमें धान एवं रबी में कैप्सिकम एवं अन्य सब्जी के साथ मछली सह बतख एवं मुर्गी पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ : नारायणपुर में एक जवान शहीद, सीएम साय ने बलिदान को किया नमन

नारायणपुर जिले में हुई मुठभेड़, नक्सलियों को घेरने गए जवान एंबुस में फंसे, कुछ जवान घायल भी हुए

श्रीकंचनपथ न्यूज

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक डीआरजी का जवान शहीद हो गया है। बताया जा रहा है कि सोनपुर और कोहकामेटा बॉर्डर के पास बुधवार को जंगल में बीएसएफऔर डीआरजी की टीम नक्सलियों के एंबुश में फंस गई थी। बुधवार दोपहर 1 बजे से दोनों ओर से रुक-रुककर फायरिंग हुई और इस दौरान जवान शहीद हो गया। वहीं कुछ जवानों के घायल भी हुए हैं। शहीद जवान के शव को लेकर पुलिस की एक टीम नारायणपुर पहुंच गई है। दूसरी टीम जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवान के बलिदान को नमन किया है।

मिली जानकारी के अनुसार अबूझमाड़ में नक्सली पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) की वर्षगांठ मना रहे थे। इनके बड़े कैडर्स भी वहां मौजूद थे। इसी सूचना के आधार पर जवानों को सर्च ऑपरेशन के लिए निकाला गया था। इस दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान नारायणपुर में हेड कॉन्स्टेबल बीरेंद्र कुमार सोरी (36) को गोली लगी, जिससे उनकी मौके पर ही शहादत हो गई। आईजी सुंदरराज पी ने इसकी पुष्टि की है। बीरेंद्र कुमार सोरी 2010 में नारायणपुर जिला बल में कॉन्स्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। 2018 में नक्सल ऑपरेशन में वीरतापूर्ण कार्य के लिए उन्हें हेड कॉन्स्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था। वे कांकेर के नरहरपुर के रहने वाले थे।

सीएम साय ने कहा- शहादत का ऋणी रहेगा राष्ट्र

जवान बीरेंद्र कुमार सोरी की शहादत को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नमन किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए हमारे जांबाज, प्रधान आरक्षक बिरेंद्र कुमार सोरी जी की शहादत को नमन करता हूं। शहीद बिरेंद्र कुमार सोरी जी नक्सल ऑपरेशन में वीरतापूर्ण कार्य के लिए पूर्व में आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत हुए थे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत पुण्यात्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले हर देशभक्त का त्याग और बलिदान, हमें देश की रक्षा के प्रति प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्र आपकी वीरता और समर्पण का सदैव ऋणी रहेगा।

बीजापुर में मुखबिरी के शक में दो पूर्व सरपंचों की हत्या, क्षेत्र में दहशत का माहौल

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों न दो पूर्व सरपंचों की हत्या कर दी है। मुखबिरी के शक में ग्राम पंचायत कडेर के पूर्व सरपंच सुखराम अवलम व बिरियाभूमि के पूर्व सरपंच सुकलु फरसा की हत्या कर दी। गंगालुर एरिया कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बिरियाभूमि के पूर्व सरपंच को मंगलवार रात को पत्नी के सामने से अगवा किया था।

मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने बीती रात एक पूर्व सरपंच की पुलिस मुखीबरी के आरोप में धारदार हथियार से हत्या कर दी है। नैमेड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कडेर के पूर्व सरपंच सुखराम अवलम उम्र 40 की नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। नक्सलियों की गंगालुर एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पर्चा छोड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

अपहरण कर पूर्व सरपंच की हत्या

मुखबिरी के शक में एक अन्य घटना में बिरियाभूमि के पूर्व सरपंच को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। मामला बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लाक के आदवाड़ा से बिरियाभूमि के बीच का है। बीते दिनों बिरियाभूमि के पूर्व सरपंच सुकलु फरसा अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक काम से आश्रित गांव आदवाड़ा गये हुए थे। वहां से वापसी के दौरान नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया। बीती रात नक्सलियों ने उनकी हत्या कर शव के पास एक पर्चा छोड़ा है। जिसमें पूर्व सरपंच को भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए उन्हें चेतावनी देने की बात लिखी हुई है। पर्चा में लिखा है कि फरसा को तीन बार चेतावनी दिया गया था। नहीं समझ पर चौथी पीएलजीए ने मौत की सजा दी है।

परिजनों व बेटी ने लगाई थी रिहाई की गुहार

सुकलु फरसा के अपहरण के बाद उसके परिजनों ने मीडिया व सोशल मीडिया के जरिये रिहाई की गुहार भी लगाई। पूर्व सरपंच की बेटी ने सोशल मीडिया से अपने पिता की सकुशल रिहाई की मार्मिक गुहार लगाई है। पूर्व सरपंच की नाबालिग बेटी यामिनी फरसा ने सोशल मीडिया के जरिये अपने पिता को निर्दोष बताते हुए उन्हें रिहा करने की मार्मिक गुहार लगाई। इसके बाद भी नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी।

छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट ने खत्म की पुलिस कर्मियों के बच्चों दी जाने वाली छूट

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 5967 पदों पर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है। बुधवार को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है। इसमें पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया गया है। शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट यथावत रहेगी। नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर जवानों के बच्चों को भी छूट मिलेगी। हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में सुनवाई हुई है।

बता दें छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के लिए 5 हजार 967 पदों पर भर्ती निकली है। पुलिस कर्मियों के बच्चों को फिजिकल में छूट मिली थी। डीजीपी ने अवर सचिव को पत्र लिखकर छूट का

प्रावधान किया था। भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। इसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स में शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिकाकर्ता के बेटे ने राजनांदगांव में कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया है।

26 नवंबर को हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक

बेदराम टंडन की याचिका पर 26 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने कहा था कि पुलिसकर्मियों के बच्चों को लाभ देना गलत है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि अपने विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को छूट देना आम लोगों के साथ भेदभाव है। वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। 8 दिन बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाया। अब फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

हैदराबाद में अल्लू अर्जुन को देखने आई भीड़ हुई बेकाबू, भगदड़ में महिला की मौत, दो घायल

हैदराबाद ए.। अल्लु अर्जुन की बहुप्रतिक्षित फिल्म पुष्पा 2 सेनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर फैन्स में दिवानगी का आलम यह है कि एक्टर की एक झलक पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। इसबीच हैदराबाद से बड़ी खबर आ रही है। अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का प्रीमियर आधी रात को हैदराबाद में रखा गया। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना खुद हैदराबाद

में आरटीसी क्रॉस रोड के संध्या थिएटर पहुंचे। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोग भी वहां पहुंचे। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके लिए प्रशासन ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य लोग जख्मी हो गए।

दिलसुखनगर की रहने वालीं रेवती अपने पति भास्कर और अपने दो बच्चों श्री तेज (9) और संविका (7) के साथ 'पुष्पा 2' का प्रीमियर शो देखने आई थीं। जैसे ही भीड़ ने गेट से धक्का दिया, शोर के बीच रेवती और उनके बेटे श्री तेज बेहोश हो गए। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, 'पीड़ित 39 वर्षीय महिला संध्या थिएटर में बेहोश हो गई थीं और उन्हें इलाज के लिए दुर्गा बाई देशमुख अस्पताल लाया गया। हालांकि, वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल श्री तेज को अच्छे देखभाल के लिए बेगमपेट के केआईएमएस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

बस्तर ओलंपिक और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम साय ने दिया निमंत्रण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसे गृह मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों की हालिया उपलब्धियों और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्यों के सम्बन्ध में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सरकार द्वारा सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के लिए किए गए प्रयासों ने स्थानीय जनता का भरोसा जीता है, जिससे माओवादी प्रभाव कमजोर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों के कारण बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों में घटनाओं में तेजी से कमी आई है। सरकार के प्रयासों से बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा बल लगातार प्रभावी अभियान चला रहे हैं, और विकास कार्यों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15,000 मकानों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सके।

हिमंत बिस्वा का धोबीपछाड़

श्रीकंचनपथ

भारतीय कुश्ती में धोबी पछाड़ एक ऐसा दांव है जिसमें विरोधी के वजन और वेग का उपयोग कर ही उसे पटखनी दी जाती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐसा ही एक दांव लगाकर अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। दरअसल, मामला है गोमांस भोज का। सामगुरी उपचुनाव का 23 नवंबर को रिजल्ट आया। नतीजे आने के बाद कांग्रेस की हार पर सांसद रकीबुल हुसैन ने भाजपा पर बीफ बांटने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि - वे राज्य में गोमांस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कांग्रेस इसे लिखित में दे। फिलहाल गोमांस के सार्वजनिक उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। अब असम के रेस्त्रां, होटल, सामूहिक भोज, आदि कार्यक्रमों में गोमांस का उपयोग वर्जित रहेगा। बड़े जानवरों का मांस एक अकेला परिवार खा नहीं सकता। अतः मान लेना चाहिए कि इस फैसले से गोहत्या पर परोक्ष रूप से लगाम लगा दिया गया है। गोमांस भारत में एक बड़ा मुद्दा है। यहां गाय को माता माना जाता है। गौवंश आजीविका का भी एक बड़ा साधन है। हिमंत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को मजबूत करेगा। यह अधिनियम उन क्षेत्रों में मवेशी वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं और किसी मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के पांच किलोमीटर के दायरे में हैं। असम में गोमांस के सेवन पर प्रतिबंध नहीं है। देश के 28 में से 20 राज्यों में गोकशी एवं गोमांस पर किसी न किसी तरह की पाबंदी है। केवल अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा एवं नगर हवेली, दमन, दीयू और पुडुचेरी में ही इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में भी इसपर प्रतिबंध था जिसे 2021 में हटा लिया गया। जहां तक भारत के गोमांस निर्यात का प्रश्न है भारत दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा बीफनिर्यातक है। पिछले साल भारत ने 1.42 मिलियन मीट्रिक टन बीफका निर्यात किया। भारत में गाय, बैल अथवा बछड़े के मांस के निर्यात पर पाबंदी है। यहां केवल भैंसा, बकरा या पोल्ट्री मीट के निर्यात की ही इजाजत है। सरकार ने इस कानून में भी संशोधन कर बोनलीस मीट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। ऐसा इसलिए कि इसके लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उससे मुंह एवं खुरों के रोग फैलाने वाले जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का केवल 32 प्रतिशत ही देसी गाय से आता है। 30 फीसदी हिस्सा विदेशी नस्ल की गायों से आता है। शेष हिस्सा भैंस से मिलता है। कैसी विडम्बना है कि दुधारू होने के कारण जो सम्मान गाय को हासिल है, वह भैंस को नहीं। भोजन के लिए बड़े जानवरों का वध जिस प्रयोजन से किया जाता था, वह तो कब की खत्म हो चुकी।

संपादकीय

देवेंद्र फिर सीएम, सही समय पर सही फैसला

राजनीति में अपनी बात मनाने के लिए रूठना पड़ता है,दिखाना पड़ता है कि आपके फैसले से हम नाराज हैं। अपने समर्थकों,वोट देने वालों को भी बताना पड़ता है कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सीएम बनने की लेकिन हालात मेरे खिलाफ था, इसलिए मैं बन नहीं सका। महाराष्ट्र में जो जनता ने महायुति के प्रचंड बहुमत दिया। इसके बाद महायुति की जिम्मेदारी थी कि वह अपनी सरकार सबकी सहमति से बनाती। आपसी सहमति बनाने में दस दिन से ज्यादा लग गए।

देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तो तय था। अजीत पवार का डिप्टी सीएम बनना भी तय था, यह भी तय था कि किस दल के कितने मंत्री बनेंगे। विभागों को लेकर कुछ विवाद हो सकता है लेकिन जिस तरह सीएम का मामला सुलझा लिया गया, उसी तरह विभागों का मामला भी सुलझा लिया जाएगा। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद तो सब चाह रहे थे कि महायुति मे जश्न का माहौल होना चाहिए। सरकार बनाने की खुशी सबको होनी चाहिए। लेकिन इस खुशी के मौके में एकनाथ शिंदे ने मुंह फुलाकर रंग में भंग डाल दिया। वह खुश नहीं दिख रहे थे, बाकी नेता जितने खुश दिख रहे थे, वह खुश ही नहीं लग रहे थे।

दिल्ली से लौटने के बाद वह अपने गांव सतारा चले गए। इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि जो पीएम मोदी व शाह चाहेंगे वही होगा, वह उसका समर्थन करेंगे। इसके बाद मुंबई लौटे तो फिर उनकी तबियत खराब हो गई और एक बयान में उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी कि जनता चाहती है कि वह फिर से सीएम बने। यानी उन्होंने अपने समर्थकों, वोटरों को बता दिया कि मैं तो सीएम बनना चाहता हूं लेकिन हालात मेरे अनुकूल नहीं है। क्योंकि ज्यादा सीटें तो भाजपा ने जीती हैं। भाजपा ने इस बार उध्दव की चालाकी से सबक लेते हुए चुनाव के पहले ही साफ कर दिया था कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा, इसका सीधा मतलब था कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, सीएम उसका बनेगा।

जनता ने सबसे ज्यादा सीटों पर भाजपा को जिताया मतलब जनादेश तो भाजपा के पक्ष में है कि सीएम तो भाजपा का ही होना चाहिए। ऐसे मे शिंदे के जनता चाहती है कि वह सीएम बने इसका कुल मतलब यह है कि वह जानते हैं कि वह सीएम किसी तरह नहीं बन सकते। लेकिन अपनी इच्छा तो जाहिर कर सकते हैं तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। देवेंद्र उनसे मिलने गए तो वह मान गए कि वह डिप्टी सीएम बनेंगे।

इससे पांच दिसंबर को सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के शपथ लेने का रास्ता तो साफहो गया है। देवेंद्रे फडणवीस को ही इस बार सीएम बनना था तो वह इसलिए कि वही महाराष्ट्र में भाजपा का चेहरा है, उन्होंने ही भाजपा को पहली बार 132 सीटों पर जिताया है। यही नहीं उन्होंने सीएम रहने के बाद पार्टी हित में अपने जूनियर लोगों की सरकार में डिप्टी सीएम बनने को राजी हुआ और ढाई साल किसी तरह की शिकायत नहीं की, किसी ने उनके व्यवहार की कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने शिंदे को ढाई साल सीएम माना, उनका पूरा सम्मान किया। इस वजह से भी वह सीएम पद के ज्यादा दावेदार माने गए।

शिंदे ने अपनी तरफ से कोशिश की कि वह सीएम रहें है, अच्छा काम किए है, इसलिए उनको सीएम रहने दिया जाए। अगर ऐसी कोई बात पहले हुई होती तो यह बात अच्छी लगती, ऐसी कोई बात पहले नही हुई थी इसलिए शिंदे के सीएम बनने का तो सवाल ही नहीं उठता था। भाजपा चाहती तो उनके चेहरे पर चुनाव न लड़कर चुनाव जीत सकती थी लेकिन भाजपा ने शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़कर उनका पूरा सम्मान किया।

अजीत पवार को महायुति में बोझ समझा जा रहा था लेकिन वह अमित शाह की प्लान बी का हिस्सा था ताकि चुनाव के बाद कोई भाजपा को ब्लैकमेल न कर सके। चुनाव में अजीत पवार ने चालीस सीटें जीतकर शाह के प्लान बी को मजबूत ही किया। अजीत पवार के कारण ही शिंदे तो कुछ दिन की नाराजगी के बाद मानना पड़ा भाजपा जो कर रही है, ठीक कर रही है। शिंदे जानते हैं कि महायुति में भाजपा की सीटें इतनी ज्यादा हैं कि उनको कोई झुका नहीं सकता। और जो उसको ठीक लगे वह कर सकती है।

भाजपा चाहती तो कबसे देवेंद्र फडणवीस को सीएम घोषित कर सकती थी लेकिन उन्होंने अकेले कोई फैसला नहीं किया। महायुति का सीएम है, इसलिए भाजपा चाहती थी कि उसमें शिंदे व अजीत की बराबर की सहमति होनी चाहिए।शिंदे के आखिरी में मान जाने से सब सामान्य हो गया है।कल शपथ ग्रहण होगा। उसके बात आपस में बात कर विभागों व मंत्रियों मामला भी सुलझाया जा सकता है। शिंदे के मान जाने से सबसे ज्यादा निराशा मोदी विरोधियों को होगी जो चाहते थे कि शिंदे बगावत कर दें और भाजपा की सरकार न बनने दें।

शिंदे नाराज तो हो सकते थे लेकिन बगावत नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर उनमें और उध्दव ठाकरे में क्या फर्क रह जाता। उन्होंने ढाई साल में खुद को उध्दव से बेहतर नेता साबित किया है. वह बेहतर नेता तब ही बने रह सकते है, जब महायुति में रहें।उनकी भलाई महायुति में बने रहने में है। उनका बेहतर भविष्य महायुति में ही रहने में है।वह भविष्य में भी नाराज हो सकते हैं किसी कारण से लेकिन वह महायुति को छोडने का जोखिम शायद ही कभी उठाएं।

पुलिस और जेल व्यवस्था

मुख्य मुद्दा यह है कि ये समस्या पैदा ही क्यों हुई है। स्पष्टतः इसकी जड़ें आपराधिक न्याय प्रक्रिया पर अमल से जुड़ी है। प्रश्न है कि क्या पुलिस और जेल व्यवस्था में बुनियादी सुधार के बिना कोई ठोस व्यावहारिक समाधान निकल सकता है? एलान सचमुच बड़ा है। आशा है कि इसके पीछे इरादा भी नेक होगा। इसके बावजूद जिस भावना से घोषणा हुई है, उसके जमीन पर उतर सकने को लेकर कुछ सवाल मौजूद हैं। एलान यह है कि ऐसे विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाएगा, जो अपनी संभावित सजा का एक तिहाई हिस्सा काट चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने धीमी न्याय प्रक्रिया से निपटने के लिए नई पहल की घोषणा की। उन्होंने दो-टूक कहा कि छोटे अपराधों के आरोप में बंद ऐसे कैदियों को जमानत दी जाएगी, जिन्होंने अपनी संभावित सजा का एक-तिहाई हिस्सा काट लिया है। इसके पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले वर्ष संविधान दिवस पर अपने भाषण में जेलों में बढ़ती भीड़ की ओर ध्यान खींचा था। उन्होंने न्याय की ऊंची लागत की समस्या का जिक्र करते हुए शासन की तीनों शाखाओं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिकाङ्क से इसका समाधान खोजने की अपील की थी।

बहरहाल, कुछ व्यावहारिक सवाल हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि ये समस्या पैदा ही क्यों हुई है। स्पष्टतः इसकी जड़ें आपराधिक न्याय प्रक्रिया पर अमल से जुड़ी है। प्रश्न है कि क्या पुलिस और जेल व्यवस्था में बुनियादी सुधार के बिना कोई ठोस व्यावहारिक समाधान निकल सकता है? फिर मसले का संबंध न्यायपालिका से भी जुड़ता है। न्यायपालिका में जजों की भारी कमी और जमानत के मौजूदा धन-आधारित मॉडल का विकल्प ढूंढे बिना उपरोक्त नेक इरादे को अमली जामा पहना सकना कठिन हो सकता है। दरअसल, आधुनिक न्याय व्यवस्था में जैसाकि कहा जाता है, बेल नियम और जेल अपवाद होना चाहिए। यानी जमानत मिलना सभी मामलों में सामान्य नियम होना चाहिए। मगर कई ऐसे मामले हैं, जिनमें राजनीतिक मकसदों से व्यक्तियों पर गंभीर इल्जाम मढ़ दिए जाते हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह चलन ज्यादा ही बढ़ गया है। ऐसे मामलों का क्या समाधान होगा? यानी समस्या का एक सूत्र सरकार के अपने नजरिए में भी है। कुल नतीजा जेलों में भारी भीड़ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 की शुरुआत तक 1,34,799 लोग सुनवाई के इंतजार में जेलों में बंद थे, जिनमें से 11,448 पांच साल से ज्यादा समय से बिना सजा के जेल में हैं।

(आरएनएस)

नजरिया

दिल्ली सल्तनत पर बार-बार क्यों करते हैं किसान चढ़ाई?

अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा? क्या उनकी मांगे भविष्य में कभी पूरी हो भी पाएंगी या नहीं? केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, हर दौर में यही सब कुछ देखने को मिलता है। कमोबेस, सरकारों का रवैया सदैव एक जैसा ही रहता है। इसलिए एकाएक किसी सरकार को दोषी ठहराना किसी टिप्पणीकार के लिए बेईमानी सा होता है। किसान आंदोलनों से जो समस्याएं उपजती हैं, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आमजन ही भुगतते हैं। समस्याएं किस कदर पनपती हैं इस ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं जाता।

डॉ. रमेश ठाकुर

मरीज, छात्र, राहगीर, दैनिक कर्मी तो बेहाल होते ही हैं, रोजमर्रा के क्रियाकलाप भी रुक जाते हैं। दो दिसंबर को भी यही हुआ, जब किसान उत्तर प्रदेश के एक छोर से चले, तो सड़कों पर दौड़ने वाले तेज वाहनों के पहिए थम गए। क्या मरीज, क्या नौकरीपेशा, सभी के पैर अपने जगह रूक गए।

दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बलपूर्वक बॉर्डरों पर ही रोका गया है। पर, हालात दिल्ली-एनसीआर के एक बार फिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं। इस दफे भी किसानों के तेवर उग्र दिख रहे हैं। अन्नदाता लंबा आंदोलन करने के मूड़ में दिखाई पड़ते हैं। इतना तय है, अगर उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं हुआ, तो हालात पिछले किसान आंदोलन जैसे बनने में वक्त नहीं लगेगा। किसान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बीते एक महीने से अल्टीमेटम दे रहे थे कि उनकी मांगे मानी जाएं, उनसे बात करे कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जिससे दोनों पक्ष बैठकर कोई हल निकाल सकें। लेकिन उनकी बातों को हुकूमती स्तर पर एक बार भी अनसुना और अनदेखा किया गया।

दिल्ली पहुंचने के लिए गौतमबुद्ध नगर से करीब 50,000 से अधिक किसान सोमवार सुबह यानी दो तारीख को नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्रित हुए, फिर उन्होंने दिल्ली कूच का प्लान किया, हालांकि तत्काल रूप से तो पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया है। लेकिन किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं, वह किसी भी सूरत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। उनको लगता है संसद का शीत सत्र चालू है। पूरी हुकूमती मशीनरी इस समय एक साथ है, उनकी बातें आसानी से पहुंच सकती है। पर, ऐसा होता दिख नहीं रहा। केंद्र सरकार इतनी आसानी से सबकुछ मान लेगी, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए किसान भी काफी उग्र हैं। अपने साथ लंबे आंदोलन को करने के लिए तामझाम लेकर पहुंच हैं। राशन, टैक्टर, मोटरसाइकिल, गैस सिलेंडर, तंबू आदि है उनके पास।

किसानों ने दिल्ली मार्च का प्लान अचानक से ही बनाया। पहले की प्री-प्लान नहीं थी। क्योंकि किसान अपनी विभिन्न मांगो को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर पिछले कुछ दिनों से धरनागत थे। उनकी प्रमुख मांगे हैं, उन्हें ज़मीन के बदले 10 पर्सेंट निर्मित प्लॉट और 64 पर्सेंट बढ़ा हुआ जमीन का शेष मुआवज़ा दिया जाए। साथ ही जितने किसान जमीन छिन जाने से भूमिहीन हुए हैं, उनके परिवार के बच्चों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई न कोई रोजगार जैसी वैकप्लिक व्यवस्थाएं की जाएं, इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। फसलों की कीमतें डबर हों, खाद, बीज व कीटनाशक दवाईयों के रेट कम किए जाएं जैसी पुरानी मांगे भी उनकी बरकरार हैं। इस वक्त मंड़ियों में धान की खरीद में जो घटतौली हो रही है उसे तुरंत रोका जाए। ये मांगे ऐसी जिसे शायद ही सरकारें मांगे।

प्रतीत ऐसा होता है कि ये किसान मूवमेंट भी बडा रूप ले सकता है। अभी तक गनीमत ये समझी जाए, इस मोर्चे में सिर्फ दर्जन भर ही किसान संगठन शामिल हुए हैं। हालांकि बाहर से करीब सौ से ज्यादा किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है। मोर्चे को रोकने को अगर कोई जल्द विकल्प नहीं निकाला गया, तो अन्य किसान संगठन भी कूदने में देर नहीं करेंगे। हालांकि सोमवार को किसान मोर्चे को देखते हुए नोएडा ट्रैफ़िक पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी की गई जिसमें कालिंदी कुंज बॉर्डर, यमुना एक्सप्रेस-वे और डीएनडी बॉर्डर से बचने की लोगों को सलाह दी गई, क्योंकि इन जगहों पर मोर्चे का असर व्यापक रूप से देखने को मिला। लोग अनचाई परेशानी से जूझते दिखाई पड़े, स्कूली बच्चों भी जाम में फंसे रहे, एमबूलेंस भी नहीं निकल पाई। नौकरीपेशा समय से अपने कार्यालयों में नहीं पहुंच पाए। ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे, जब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा।

किसान मूवमेंट शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही राजनीति भी आरंभ हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने कहा दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण गाड़ियां और अमित शाह की पूरी पुलिस तैनात की गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे की उनको किसी आंतकवादी को रोकना या पकड़ना हो? किसान भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवज़ा और फसल के सही दाम की मांग लेकर दिल्ली आकर सोती सरकार को जगाना चाहते हैं इसमें बुरा क्या है? वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से बयान आया जिसमें कहा गया कि राष्ट्र की राजधानी किसी की बपौती तो है नहीं? फिर किसान क्यों नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने हमला किया। बोले, किसानों पर बर्बरता के नए आयाम रच रहे हैं प्रधानमंत्री। उनके दिल में अन्नदाताओं के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें आने देना चाहिए, उनपर वाटर कैनन का प्रयोग करना गलत है। दरअसल, ऐसे मौकों पर विपक्ष का बिना सोचे समझे कूद पड़ना, 'आग में घी डालने' का काम कर जाता है। जबकि, उन्हें केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर विकल्प और समाधान की ओर ध्यानाकर्षण करवाना चाहिए। ताकि सरकार आंदोलनकारियों से बात करने पर विवश हो? पर, दुर्भाग्य ऐसा हो नहीं पाता और न ही विपक्ष ऐसा प्रयास करता है।

(ये लेखक के विचार हैं)

इच्छा शक्ति से ही नियंत्रित हो सकेगा प्रदूषण

रजनीश कपूर

हम और आप जब भी कोई वाहन ख़रीदते हैं तो हम उस वाहन की कीमत के साथ-साथ रोड टैक्स, जीएसटी आदि टैक्स भी देते हैं। इन सब टैक्स देने का मतलब हुआ कि यह सब राशि सरकार की जेब में जाएगी और घूम कर जनता के विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। परंतु रोड टैक्स के नाम पर ली जाने वाली मोटी रकम क्या वास्तव में जनता पर ख़र्च होती है?

बीते कुछ सप्ताह से दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत को प्रदूषण के बादलों ने घेर रखा है। इससे आम जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सरकार ने कई तरह की पाबंदियाँ लगा दी हैं। इसके चलते असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इन पाबंदियों के चलते कई रोजगारों पर भी असर पड़ने लगा है। निर्माण कार्य में लगे दिहाड़ी मजदूर वर्ग इन पाबंदियों के चलते सबसे अधिक परेशान है।

तमाम टीवी चैनलों पर प्रदूषण के बिगड़ते स्तर पर काफी बहस हो रही है। परंतु क्या किसी ने हमारे देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सही व ठोस कदम उठाने की बात की है? क्या केवल निर्माण कार्यों और वाहनों पर प्रतिबंध से प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी? ऐसे अनेकों कारण हैं जिन पर अगर सरकार ध्यान दे तो प्रदूषण में नियंत्रण पाया जा सकता है। सबसे पहले बात करें वाहन प्रदूषण की। इस बात पर इसी कॉलम में कई बार लिखा जा चुका है कि एक विशेष आयु या श्रेणी के वाहन को प्रतिबंध करने से क्या प्रदूषण में कमी आएगी?

इसका उत्तर हाँ और नहीं दोनों ही है। यदि कोई वाहन, जो कि पुराने माणकों पर चल रहा है और उसके पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है तो निश्चित रूप से ऐसे वाहन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। परंतु यदि वही वाहन प्रदूषण के तय माणकों की सीमा में पाया जाता है तो उसे प्रतिबंधित करने का क्या औचित्य है? हम और आप जब भी कोई वाहन खरीदते हैं तो हम उस वाहन की कीमत के साथ-साथ रोड टैक्स, जीएसटी आदि टैक्स भी देते हैं।

इन सब टैक्स देने का मतलब हुआ कि यह सब राशि सरकार की जेब में जाएगी और घूम कर जनता के विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। परंतु रोड टैक्स के नाम पर ली जाने वाली मोटी रक़म क्या वास्तव में जनता पर ख़र्च होती है? क्या हमें अपनी महँगी गाडियों को चलाने के लिए साफ़-सुथरी और बेहतरीन सड़कें मिलती हैं? टूटी-फूटी सड़कों की समय-समय पर मरम्मत होती है? क्या देश भर में सड़कों की मरम्मत करने वाली एजेंसियाँ अपना काम पूरी निष्ठा से करतीं हैं? इनमें से अधिकतर सवालों के जवाब आपको नहीं में ही मिलेंगे।

टूटी-फूटी सड़कों पर वाहन अवरोधों के साथ चलने पर मजबूर होते हैं, नतीजा जगह-जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसे जाम में खड़े रहकर आप न सिर्फ अपना समय जाया करते हैं बल्कि महँगा ईंधन भी ज़ाया करते हैं। जितनी देर तक जाम लगा रहेगा, आपका वाहन बंपर-टू-बंपर चलेगा और बढ़ते हुए प्रदूषण की आग में घी का काम करेगा। ऐसे में जिन वाहनों को पुराना समझ कर प्रतिबंधित किया जाता है, उनसे कहीं ज्यादा मात्रा में नये वाहनों द्वारा प्रदूषण होता है। इसलिए लोक निर्माण विभाग या अन्य एजेंसियों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह सड़कों को दुरुस्त रखें जिससे प्रदूषण को बढ़ावा न मिले।

इसके साथ ही ट्रैफिक नियंत्रण की समस्या भी एस समस्या है जिससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। मिसाल के तौर पर आपको आपके शहर में ऐसे कई चौराहे मिल जाएँगे जहां लाल-बत्ती की अवधि जरूरत और ट्रैफिक के प्रवाह के अनुसार मेल नहीं खाती। नतीजा, ऐसे चौराहों पर ट्रैफिक की लंबी कतारें। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही ऐसे चौराहों पर लंबी कतारें लगती हैं। ज्यादातर कतारें ट्रेफिक के पीक घंटों में लगती हैं। यदि उस समय ट्रैफिक पुलिस द्वारा चुनिंदा चौराहों को नियंत्रित किया जाए तो जाम की समस्या पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। इसके लिए कुछ मामूली से ही परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

आज गूगल मैप पर आप घर बैठे ही हर गली नुक्कड़ का ट्रैफिक देख सकते हैं। यदि् लान कर सकते हैं तो ट्रैफ़िक कंट्रोल रूम के अधिकारी, संबंधित इलाके के ट्रैफिक अधिकारी को इस समस्या के प्रति झकझोर क्यों नहीं सकते? ट्रैफिक को नियंत्रित करने के जैसे, ही प्रदूषण के अन्य कारकों पर भी लगाम कसी जा सकती है। जरूरत है तो इच्छा शक्ति की। यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2010 में जब हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था तो दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि ट्रैफ़िक जाम नहीं होते थे।

जगह-जगह पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ट्रैफिक पर पैनी नजर बनाए हुए थे। यानी डंडे के जोर पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा रहा था। यदि एक ट्रैफिक की समस्या को डंडे के जोर पर, किसी विशेष इंतजाम के लिए नियंत्रित जा सकता है तो आम दिनों में क्यों नहीं? अब बात करें दीपावली के बाद हर वर्ष होने वाली पराली जलाए जाने की। यह बात जाग-ज़ाहिर है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान हर वर्ष इन्हीं दिनों पराली जलाते हैं। यह समस्या हर वर्ष प्रदूषण का कारण बनती है। हर वर्ष बड़ी-बड़ी बातें और घोषणाएँ की जाती हैं लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते।

यदि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो या कोविड के दौरान लॉकडाउन लागू करना हो, जब इन्हें सख़्ती से लागू किया जा सकता है तो पराली को जलाने से क्यों नहीं रोका जा सकता? ठीक उसी तरह कारख़ानों से निकलने वाले धुएँ को भी नियंत्रित करना असंभव नहीं है। सरकार चाहे तो इस राह में ठोस कदम उठा कर प्रदूषण को नियंत्रण में ला सकती है। केवल नारों, घोषणाओं और प्रतिबंधों से नहीं इच्छा शक्ति से ही नियंत्रित हो सकेगा प्रदूषण। जहां चाह वहाँ राह!

(ये लेखक के विचार हैं)

काम से नीयत का पता चलता है

कोई सरकार कोई काम करती है। उसकी नीयत का पता उसके काम से ही चल जाता है कि यह जो काम कर रही है ठीक कर रही है या गलत कर रही है।हर सरकार के समय भ्रष्टाचार होता है, सरकार काम से पता चल जाता है कि सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ कर रही है या भ्रष्टाचार होने देने के लिए कुछ रही है। जो सरकार भ्रष्टाचार रोकना चाहती है वह अपने काम से भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करेगी और जो सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है या भ्रष्टाचार होने देना चाहती है कि वह ऐसा काम करेगी जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। भूपेश सरकार व साय सरकार में सबसे बड़ा अंतर ही यही है कि एक के समय भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया गया, इसका परिणाम हुआ है खूब भ्रष्टाचार हुआ, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ। इससे सरकार भी बदनाम हुई और कांग्रेस भी बदनाम हुई। पीएससी में भाईभतीजावाद के कारण ही तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। यह बात को भूपेश सरकार भी जानती थी और साय सरकार भी जानती है। भूपेश सरकार ने क्या किया,वर्ष 2021 में परिवार शब्द की परिभाषा को संकुचित किया ताकि भाईभतीजावाद आसानी हो सके।

इसका परिणाम क्या हुआ,राज्य सेवा परीक्षा 2021 में भाई-भतीजावाद का आरोप लगा। पीएससी की चयन सूची में कई अफसरों, नेताओं के रिश्तदारों के नाम आए।इसे लेकर युवाओं ने आरोप लगाया कि अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए अफसरों ने नियमों की अनदेखी की। भूपेश सरकार कई साल रही लेकिन उसने ऐसे नियम नहीं बनाए जिससे पीएससी में भ्रष्टाचार रुक सके। जबकि पीएससी घोटाले की जांच करा रही साय सरकार ने पीएससी में भाई-भतीजावाद जिसके कारण होता है, उसे रोकने के लिए नया नियम बनाया है। नए नियम के मुताबिक हर परीक्षा से पहले पीएससी के अफसरों व कर्मियों को यह साफ करना होगा कि उनका कोई रिश्तेदार यहां तक कि जान पहचान वाला भी पीएससी में शामिल नहीं हो रहा है। अगर किसी अफसर या कर्मी के रिश्तेदार या परिचित पीएससी की परीक्षा दे रहा है तो उस अफसर व कर्मी को परीक्षा से बाहर रखा जाएगा यानी पीएससी की परीक्षा में उसकी कहीं कोई भूमिका नहीं होगी।साय सरकार आने के बाद राज्य सेवा परीक्षा 23 से यह व्यवस्था लागू हो गई है।

आगे भी यह लागू रहेगी। परिवारवाद के आरोप के बीच पीएससी में होने वाले भ्रष्टाचार रोकने के लिए साय का यह सराहनीय कदम माना जा रहा है।पीएससी परीक्षा के लिए साय सरकार से पहले यानी भूपेश सरकार के समय परिवार शब्द का आशय खून के रिश्ते से था।इसमें माता-पिता, पुत्र-पुत्री,नाती-पोता आदि आते थे। साय सरकार ने परिवार शब्द का आशय खून के रिश्त तो हैं ही,इसके साथ ही निकटतम रिश्तेदार, परिचित को शामिल कर दिया है। जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है, वह पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार से सबक लेती है जिन कारणों से पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुए, उन कारणों का जानने का प्रयास करती है और ऐसी व्यवस्था करती है कि पिछली सरकार के समय जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए, इस सरकार में न हो। पिछली सरकार के समय भारी शराब घोटाला हुआ। साय सरकार ने आबकारी विभाग की उन नीतियों को बदल दिया जिनके कारण भ्रष्टाचार होता था। यही काम साय सरकार ने पीएससी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए परिवार शब्द का दायरा बढ़ा दिया है ताकि कोई परिवार का कोई व्यक्ति परीक्षा दे रहा है तो उसका रिश्तेदार को परीक्षा के दायरे से बाहर रखा जाए ताकि पीएससी में कोई भाई-भतीजावाद न हो। पीएससी में भ्रष्टाचार भाई-भतीजावाद के कारण ही होता था, पिछली सरकार भी जानती थी इसे कैसे रोका जा सकता है लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। यह काम साय सरकार ने किया तो इससे राज्य के युवाओं का साय सरकार प्रति भरोसा बढ़ेगा। उनको लगेगा कि अब राज्य की पीएससी परीक्षा में कोई भाइ-भतीजावाद नहीं होगा। कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा।

(आरएनएस)

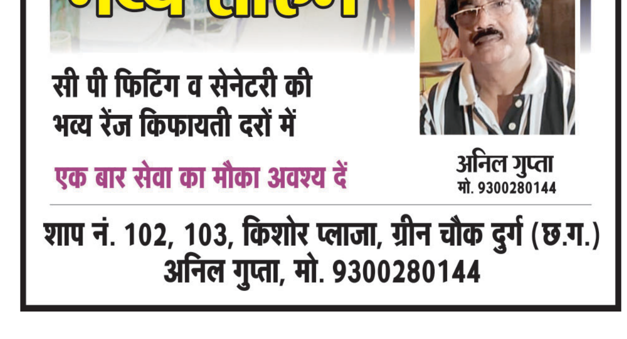

श्रीकंचनपथ

भिलाई–दुर्ग

खास खबर

नगर सेवाएं विभाग में राजभाषा कार्यशाला आयोजित

भिलाई। बीएसपी के नगर सेवाएँ विभाग में मुख्य महाप्रबंधक उत्पल दत्ता के मुख्य आतिथ्य में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सहायक महाप्रबंधक एवं विभागीय राजभाषा समन्वय अधिकारी यशवंत कुमार साहू ने बताया कि, नगर सेवाएँ विभाग का पत्राचार विभिन्न बाह्य एजेंसियों जैसे व्यवसायियों, आपूर्तिकर्ताओं तथा प्रशासन आदि से होता है, जिसमें विभाग द्वारा शत-प्रतिशत हिंदी में पत्राचार किया जाता है। हिंदी को प्रोत्साहन के लिये विभागीय स्तर पर नियमित रूप से विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। प्रतियोगिताओं के क्रम में नगर सेवाएँ विभाग द्वारा नवंबर माह में हिंदी में नोटशीट लेखन प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। कार्यक्रम में राजभाषा विभाग द्वारा पर्यावरण, सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

कलेक्टर चौधरी की अध्यक्षता में जिला क्रीडांगन निर्माण समिति की बैठक सम्पन्न

दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में जिला क्रीडांगन निर्माण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने जिला क्रीडांगन समिति में नए सदस्यों के मनोनयन, रविशंकर स्टेडियम के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य, लीज प्रक्रिया, युवा उत्सव आयोजन एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा कर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। बैठक में जिला क्रीडांगन समिति में नये सदस्यों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव रखा गया, जिस पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव, विधायक अहिवारा डोमनलाल कोर्सेवाड़ा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल भी उपस्थित थे। कलेक्टर चौधरी ने अवगत कराया कि रविशंकर स्टेडियम को 33 साल के लिए बीसीसीआई को लीज पर दिया जाएगा। बीसीसीआई द्वारा स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा जिससे खेल के क्षेत्र में इसे नई पहचान मिलेगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देषित करते हुए कहा कि स्टेडियम में खेल के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम या स्टेडियम के आस-पास अन्य असमाजिक गतिविधियां न हो इस बात का विषेष ध्याान रखा जाए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में जनवरी माह में प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होना है। इसको देखते हुए जनवरी के पहले स्टेडियम में आवश्यक निर्माण कार्य एवं जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कराए जाएं। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने विकासखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय स्तरीय युवा उत्सव आयोजन के संबंधित तैयारियों एवं गतिविधियों की जानकारी ली। खेल एवं विकासखण्ड नोडल अधिकारी ने आयोजन स्थल एवं आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा खेल गतिविधियों में गढ़वा बाजा को शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के आयोजन में मोहरी वादन को जोड़ा जाएगा।

संपदा न्यायालय के आदेश पर बेदखली की कार्यवाही निरंतर जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल–भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के प्रवर्तन अनुभाग द्वारा आज 04 दिसम्बर 2024 को अवैध कब्जेधारियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए टाउनशिप के 15 बीएसपी आवासों में पुलिस प्रशासन के सहयोग से बेदखली कार्यवाही की गई। प्रवर्तन विभाग द्वारा सेक्टर–6 के ग्यारह आवास, सेक्टर–1 का एक आवास, सेक्टर–2 का एक आवास, सेक्टर–7 का एक आवास तथा रिसाली सेक्टर के एक आवास को खाली करवाया गया तथा सभी रिक्त आवासों में से कुछ आवास को रखरखाव कार्यालय, कुछ को आवंटी तथा कुछ आवासों को माननीय संपदा न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि संपदा न्यायालय से डिक्री पारित तीन आवासों में बेदखली की कार्यवाही लंबित थी, इन आवासों में बेदखली पष्चात विद्युत विभाग द्वारा विद्युत विच्छेद किया गया। इन आवासों को दलालों, भू माफियाओं, अपराधियों द्वारा किराया पर चलाया जा रहा था।

ऐसे अनेक अवैध कब्जाधारी जिनके विरुद्ध माननीय संपदा न्यायालय, डिक्री आदेष पारित कर जा चुकी है, परन्तु डिक्री पारित होने के बावजूद लंबे समय से अवैध कब्जे को खाली नहीं कर रहे है। इनके द्वारा अपने अवैध कब्जे

को बनाये रखने जेबी संगठन बनाकर जुलूस नुमा शक्ल में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। सेवानिवृत्ति के बाद भी कुछ समय तक इन आवासों में निवास करने की भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की कल्याणकारी योजना का अनुचित लाभ लेते हुए ऐसे अवैध कब्जेधारियों के द्वारा आवास खाली नहीं करने के वजह से बीएसपी कार्मिकों को उच्च श्रेणी के आवास नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही संयंत्र प्रबंधन को ऐसे कल्याणकारी योजना पर पुनर्विचार के लिए बाध्य किया जा रहा है।

इसके अलावा न्यायालीन प्रक्रिया के तहत जारी बेदखली आदेश को जातिवाद का रंग देकर भिलाई की शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है। न्यायलयीन प्रक्रिया के तहत निष्पादित कार्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी ना केवल संवैधानिक प्रणाली पर अनास्था को प्रदर्शित करता है वहीं आधारहीन टिप्पणी कर माननीय न्यायालय की अवमानना की जा रही है। लोक कल्याणकारी संगठन चलाने वाले लोग स्वयं अवैध कब्जाधारी है। सरकारी आवासों को खाली करने के बजाय इन अवैध कब्जेधारियों द्वारा हठधर्मिता दिखाते हुए अवैध कब्जे खाली नहीं कर अन्य अवैध कब्जेधारियों को बीएसपी आवासों को खाली नहीं करने हेतु उकसाया भी जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रिटेंशन आवास रिटायरमेंट के पश्चात निर्धारित समय सीमा जो कि अलग-अलग योजना में अलग अलग होती है यह किसी योजना में दो वर्षों, किसी में एक वर्ष तथा कुछ महीने की है। इस समय अवधि के समाप्ति को कई वर्षों से अधिक हो चुके है तथा माननीय संपदा न्यायालय द्वारा इनका मकानों का आबंटन रद्द कर इनके विरुद्ध बेदखली कार्यवाही हेतु डिक्री पारित किया जा चुका है।

कब्जेधारियों और भू-माफियाओं के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। 04 दिसम्बर 2024 को प्रवर्तन विभाग द्वारा ठेला माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दस ठेलों को टाउनशिप के विभिन्न सेक्टर्स से जप्त किया गया। इन ठेलों के वजह से आवागमन बाधित होने के साथ सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी। इसके अलावा टाउनषिप में अवैध रूप से लगाए गए बैनर व पोस्टर हटाए गए। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु मिराज सिनेमा तथा जवाहर उद्यान के आस-पास से कुल 15 आवारा मवेशियों को पकड़ कर भिलाई नगर निगम द्वारा संचालित कोसा नगर गौठान को सौंपा गया।

सुकन्या समृद्धि योजना-बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित प्रयास, अभियान चलाकर 10340 बालिकाओं का खाता खुलवाया

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत 06 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक बालिकाओं का खाता खोलने हेतु अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में बेटियों की शिक्षा और भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है।

महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में माह नवम्बर 2024 में सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत महतारी वंदन योजना से लाभांवित हो रही महिलाओं के सहयोग से 10340 बालिकाओं का खाता खुलवाया गया।

अब तक वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14887 बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत खाता खुलवाया जा चुका है। जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सांतरा एवं अचानकपुर में लगभग सभी बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया जा चुका है। इस अभियान में महिला एवं

बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय शर्मा, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी शैल ठाकुर तथा समस्त परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया है।

योजना के क्रियान्वयन के तहत, जिले के 59 सेक्टरों में डाकघरों की मदद से 118 विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। जिसमें अभिभावकों को योजनाओं की जानकारी दी गई और बेटियों के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर जानकारी दी गई और लोगों को प्रोत्साहित किया गया। जिला प्रशासन ने अपील की है कि अधिक से अधिक अभिभावक इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को सशक्त बनाएं। सुकन्या समृद्धि योजना- बालिकाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा व विवाह हेतु बचत को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना संचालित है।

इस योजना के अंतर्गत खाता बालिका के नाम पर 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खोला जा सकता है एवं एक बालिका के नाम पर एक ही खाता डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रूपये एवं अधिकतम जमा राशि 1.50 लाख रूपये है। इसमें ब्याज दर सामान्य ब्याज दरों की तुलना में अधिक होती है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी और सहायता के लिए नजदीकी डाकघर या आंगनबाड़ी केंद्र/एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय/महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग से संपर्क कर सकते है।

कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्र कोड़िया एवं बोरीगारका का किया निरीक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कोड़िया एवं बोरीगारका के धान खरीदी केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोड़िया में स्थित सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक एवं किसानों से चर्चा की। समिति प्रबंधक ने बताया कि कल से धान उठाव का कार्य प्रारंभ होना है।

किसानों को समय सीमा के भीतर भुगतान किया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में बारदाने भी उपलब्ध है। कलेक्टर चौधरी ने समिति प्रबंधक से कहा कि छोटे किसानों को धान बिक्री प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने समिति प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी को प्रति सप्ताह स्टॉक सत्यापन कराए जाने हेतु निर्देशित किया।

उन्होंने पीडीएस प्रक्रिया से संबंधित समस्या का भी शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर चौधरी ने उपस्थित कृषकों की समस्या सुनी और उन्हें आश्वासित किया कि टोकन की समस्या का निराकरण शासन स्तर पर किया जाने का प्रावधान है। टोकन कटने में आने वाली ऑनलाईन समस्या के निराकरण हेतु शासन से चर्चा की जाएगी। उन्होंने धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों का सही संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी खाद्य नियंत्रक टी.एस. अत्री, डी.एम.ओ. भौमिक बघेल व अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

बीएसपी द्वारा शहर के चौकों के नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र, इस्पात नगरी के सौंदर्यीकरण के लिए इन दिनों कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इन परियोजनाओं के तहत, सड़कों की मरम्मत एवं चैकों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भिलाई इस्पात संयंत्र शहर के सौंदर्यीकरण और अपनी टाउनशिप को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहता है।

इसी क्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा शहर के चैकों के नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत 03 दिसंबर 2024 को रेल चैक के नवीनीकरण का कार्य

शुरू किया गया है। रेल चैक की बनावट में ग्लोब के बड़े आकार के कारण इसे जनसामान्य द्वारा ग्लोब चैक के नाम से भी जाना जाने लगा थाद्य जिसका आकार नवीनीकरण पश्चात अपेक्षाकृत छोटा किया जाएगा।

चौकों के नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के क्रम में डाइरेक्टर्स बंगले के समीप तालपूरी चैक के नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही रुआबांधा समीप पंथी चैक तथा बोरिया गेट के आगे, 30 एम एल डी ट्रीटमेंट प्लांट चैक के नवीनीकरण समेत भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट के सामने चैराहे, जिसमें भारत और सोवियत संघ की मित्रता और सहयोग के स्मारक-स्तंभ स्थापित है, का सौंदर्यीकरण एवं चैराहे का उन्नयन बीएसपी प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। इस चैराहे के घेरे को सभी तरफसे 1.5 मीटर घटाई जायेगी, इससे आवागमन सुगम होने के साथ-साथ दुर्घटना की आशंकाएं भी न्यूनतम हो जायेगी। इस स्मारक-स्तंभ के चारों तरफ चैराहे की चैड़ाई को कुल 3 मीटर कम की जायेगी।

विदित हो कि संयंत्र के 25 मिलियन टन स्टील के संचयी उत्पादन को चिह्नित करने हेतु स्मरणीय प्रतीक के रूप में एक स्मारक के रूप में स्थापित 25 मिलियन टन चैक सेक्टर 4, पंडित रविशंकर शुक्ल चैक सेक्टर 09, सेक्टर 08 चैक, जे पी चैक सेक्टर 06 के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके साथ ही जयंती स्टेडियम व नगर सेवाएं विभाग के समीप कलाकार श्री जतिन दास द्वारा निर्मित 'फ्लाईट ऑफ स्टील' मॉडल के भी निर्माण का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है, जिसे शहरवासियों के लिए एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा टाउनशिप में इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों में विशेषकर सडकों व शहरी मार्गों के कार्यों में सार्वजनिक सुविधा, शासन एवं कानून व्यवस्था, जोखिम व दुर्घटना रोकथाम आदि विषयों पर समुचित ध्यान दिया जाता है। इस यथास्थिति में, शहरीकरण के बढ़ते दबाव और टाउनशिप व निकटवर्ती क्षेत्रों में दुपहिया व चारपहिया वाहनों की बढ़ती हुई संख्या व लोगों में तेज वाहन-चालन के रुझान की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, टाउनशिप के मुख्य मार्गों पर ट्राफिक नियंत्रण तथा जोखिम व दुर्घटना रोकथाम की दिशा में सुनियोजित नवाचार व सुविधाओं की प्रतिपूर्ति को संबोधित किया जा रहा है। जिसके तहत मुख्य चैराहों पर यातायात नियंत्रण हेतु ट्राफिक सिग्नल व दुर्घटना रोकथाम हेतु उच्च गुणत्ता-युक्त कैमरे आदि लगाये जा रहें हैं।

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे आयुक्त, बच्चों को पढ़ाया

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित किया जा रहा है। नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय प्रात: स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खम्हरिया का औचक निरीक्षण करने पहुंचे।

उन्होने स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओ को बारीकी से देखा। कि विद्यार्थियो को किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। साथ ही स्कूल में बैठने के टेबल.कुर्सी, पीने का पानी, शौचालय, लाईट, पंखा आदि को अच्छे तरह से निरीक्षण किये, जिससे स्कूल में

पढने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को किसी प्रकारी की परेशानी तो नहीं हो रही है। निगम आयुक्त स्कूल का पुरी तरफ से निरीक्षण करने पश्चात बच्चो के क्लास रूम में गये। वहां पर देखे की सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे है। टीचर्स भी अच्छी तरह से पढा रही थी। आयुक्त पाण्डेय ने विद्यार्थियो की किताब को हाथ में लेकर कुछ सवाल किये, उनसे प्रश्न करने लगे और बच्चे बड़े ही जोश भरे आवाज से जवाब दे रहे थे। बच्चों से उनके क्लास के अनुसार सवाल कर रहे थे, जैसे राष्ट्रगान कितने सेकंड में पढ़ना चाहिए, राजिम कौन से जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, बांग्लादेश कौन से दिशा में है, बच्चों से गणित एवं अंग्रेजी के प्रश्न भी पूछे क्लास में रीडिंग कराते हुए कविता पूछे। यह भी सवाल था कि कौन-कौन बच्चे घर से सुबह खाना खाकर नहीं आते हैं। कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया उपस्थित शिक्षिका से उनके पेरेंट्स को समझने को कहा की बच्चों को सुबह नाश्ता कराके ही स्कूल भेजा करें । आयुक्त ने बच्चो से कहा किसी भी प्रकार का प्रश्न को अपने मन में रहने नहीं देना चाहिए। बेजिझक अपने क्लास टीचर्स से पूछना चाहिए, क्योकि प्रश्न करने से ही उसका जवाब मिलता है। दूसरे छात्र को भी पता चलता है।

खुली संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन

भिलाई। बीएसपी के क्रीडा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएँ विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित खुली संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 20 दिसम्बर 2024 के मध्य महात्मा गांधी कलामंदिर सिविक सेंटर, भिलाई निवास में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कर्नाटक, हिन्दुस्तानी , लोक गायन, एकल नृत्य , हिन्दुस्तानी वाद्य तथा खुली आयु वर्ग समूह में नृत्य स्पर्धा का आयोजन होगा। आयु समूह को दो वर्गों में 6 से 12 वर्ष एवं 13 से 18 वर्ष में विभक्त किया गया है। कोई भी प्रतिभागी मात्र दो ही विधा में भाग ले सकता है। प्रतियोगिता हेतु प्रवेश पत्र 13 दिसम्बर 2024 तक प्रदान किये जायेंगे।

खास खबर...

कल से जिला स्तर युवा उत्सव का आयोजन होगा सभी विकासखण्ड में

रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस भी युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह 06 दिसम्बर से 10 दिसम्बर तक होगा जो सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन आरंग, अभनपुर, तिल्दा, धरसींवा में किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 15 से 29 वर्ष के युवा शामिल हो सकते हैं।

युवा उत्सव में लोकनृत्य सामूहिक, लोकगीत सामूहिक, लोकर्नतय व्यक्तिगत, लोकगीत व्यक्तिगत, कहानी लेखन, चित्रकला, वक्तृत्व कला या तत्कालिक भाषण कविता, विज्ञान मेला, हस्तशिल्प, टेक्सटाईल, कृषि उत्पाद, तथा रोकबैंड भी इत्यादि विघा शामिल होगें। राक बैंड सिर्फ जिला और राज्य स्तर पर होगा। यह 06 दिसम्बर को अभनपुर विकासखंड में दावड़ा इंटरनेशनल स्कूल अभनुपर, धरसींवा में इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम परसतराई आरंग में आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, तिल्दा मे मीडिल स्कूल ग्रांउड तुलसी नेवरा में होगा।

विकासखण्ड स्तरीय स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकार जिला स्तरीय एवं जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकार/ प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। पंजीयन हेतु दयानंद देवांगन- 9302160384, विकास यादव - 9584618747, छत्रधारी सोनकर- 9399277220, जयप्रकाश टण्डन- 9575619122, 87770668542 मोबाइल नंबर पर सम्पर्क किया जा सकता है।

धान खरीदी केंद्र बिलाड़ी प्रभारी अनिमितता के चलते हटाए गए

रायपुर। रायपुर जिला में धान खरीदी केन्द्र बिलाड़ी में विजिट के दौरान सहकारिता विभाग के जिला अधिकारी एनआर के चन्द्रवंशी द्वारा पाया गया कि धान उपार्जन केन्द्र बिलाड़ी के प्रभारी मुकेश बैष्णव द्वारा बिना डनेज के धान का स्टेकिंग कर दिया गया है। जबकि शासन की उपार्जन नीति में प्रावधान है कि धान का स्टेकिंग डनेज के ऊपर किया जाए। इस प्रकार मुकेश वैष्णव द्वारा धान उपार्जन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से उपार्जन केन्द्र प्रभारी बिलाड़ी से हटा दिया गया है।

रायपुर जिले में 13 हजार 408 टन धान की हुई खरीदी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जिले के किसानों को समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। जिले में आज 13 हजार 408 टन धान की खरीदी की गई। जिले में आज 3 हजार 25 किसानों से 30 करोड़ 85 लाख रूपये धान की खरीदी हुई। इस प्रकार अब तक 139 उपार्जन केन्द्रों में 36 हजार 112 किसानों से 01 लाख 52 हजार 403 टन धान की खरीदी हुई है। इन किसानो से अब तक 350 करोड़ 75 लाख रूपये की धान की खरीदी की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर धान केन्द्रों में किसानों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। जिससे किसानों में धान बेचने को लेकर उत्साह है।

शबरी कल्याण आश्रम की छात्राओं ने राज्यपाल रमेन डेका को दी असम-नागालैंड राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएँ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से शबरी कल्याण आश्रम की छात्राओं ने भेंटकर उन्हें असम और नागालैण्ड राज्यों के स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएँ दी। केन्द्र सरकार के एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के राजभवन में असम और नागालैंड राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संगम है। विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे के स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी कड़ी में राजभवन के दरबार हॉल में असम एवं नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल ने स्थापना दिवस के अवसर पर इन राज्यों के लोगों को बधाई दी। रायपुर में वनवासी कल्याण परिसर द्वारा संचालित शबरी कल्याण आश्रम में पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरूणांचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा की लगभग 40 बालिकायें अपनी पढ़ाई कर रहीं हैं। राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर इन बालिकाओं ने वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत संगठन मंत्री रामनाथ कश्यप के साथ राजभवन पहुँचकर राज्यपाल श्री डेका से भेंट की। इस अवसर पर इन बालिकाओं ने पूर्वोत्तर राज्यों की लोक कला और लोक नृत्यों का प्रस्तुती भी दी। शबरी कल्याण आश्रम की ओर से इन बालिकाओं ने राज्यपाल श्री डेका को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। राज्यपाल ने सभी बालिकाओं का छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा पहनाकर स्वागत किया।

राज्यपाल श्री डेका ने अपने उद्बोधन में असम और नागालैंड राज्य की विशेषताओं को रेखांकित किया। राज्यपाल ने कहा कि असम और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अर्थवयवस्था मिलती-जुलती है। असम की चाय की स्फूर्तिदायक खुशबू पूरी दुनिया में फैली है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक वातावरण भी चाय उत्पादन के लिए अनुकूल है। इसलिए इस दिशा में प्रयास किया जाएगा जिससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। श्री डेका ने नागालैंड को जीवंत रंगों और बहादुरी की विशेषताओं वाला राज्य बताते हुए कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में रानी गैडिनल्यू सहित असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया। नेताजी सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज भी नागालैण्ड आई और यहां कई स्थानों पर स्वतंत्रता आंदोलन किए गए।

कार्यक्रम को असम राज्य के प्रतिनिधि के रूप में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा और नागालैंड की प्रतिनिधि सुश्री संगमाई ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा सांसद नत्थूभाई पटेल, राज्यपाल के सचिव यशंवत कुमार, राजभवन के अन्य अधिकारी, रायपुर महानगर वनवासी कल्याण आश्रम की श्रीमती संगीता चौबे तथा दोनों राज्यों के प्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन चिन्ह के संबंध में जानकारी देने हुई डीलर संगोष्ठी का आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल एसोसियेशन (फाडा) एवं रायपुर ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसियेशन (राडा) के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को हॉटल मयूरा, जीई रोड में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन चिन्ह के संबंध में अपने डीलर व्यवसायियों के लिये एक डीलर संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें जारी दिशा निर्देशों के तहत केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर यान 1989 के प्रावधानों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन पर चर्चा की गयी।

इसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के 1 अप्रैल 2019 से पहले विक्रय सभी वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए सरकार द्वारा नंबर प्लेट उपलब्ध करने के लिये मेसर्स रियल बेजान इंडिया लिमिटेड और रोसमार्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया गया है और प्रदेश के सभी अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलर को इसे लगाने के लिये अधिकृत किया गया है इस आयोजन में इन दो कंपनियों को रोज़मार्टा और रियल माज़ोन के अधिकारियो को आमंत्रित किया गया इन अधिकारियो ने एचएसआरपी नंबर प्लेट वाहन मालिक द्वारा आर्डर करने व् डीलर द्वारा लगाने के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की।

- * हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड होता है।
- * हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में लेजर युक्त यूनिक सीरियल नंबर होता है।
- * हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में अशोक चक्र का 3डी होलोग्राम होता है।
- * हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की बाई और के ऊपरी कोने पर क्रोमियम बेस्ट होलोग्राम होता है।
- * इसमें भी कल आईडेंटिफिकेशन नंबर लेजर ऐड कोडेड होता है ।
- * इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में दो नॉन रियुजेबल लॉक होते हैं।
- * अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए, वाहन स्वामी को एचएसआरपी लगाना अनिवार्य होगा। नोटीफिकेशन के 120 दिन के भीतर वाहनों (19/03/2025 तक) एचएसआरपी लगाना आवश्यक होगा ।
- * एचएसआरपी हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा 7
- * मोटरयान अधिनियम 1988 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनाल्टी से बचने के लिए केन्द्रीय मोटस्यान नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली एचएसआरपी / समान दिखने वाली प्लेटे / स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम/ इंडिया मार्क/इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) प्लेट से बदलना होगा अनिवार्य होगा।
- * अनाधिकृत रूप से एचएसआरपी की बिकी और आपूर्ति करते पाए जाने वाले डीलरों या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
- * हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर लगेगा जुर्माना।
- * वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे होने से वाहन वाहन मालिक को कई तरह से सुविधा मिलती है ।

आपको बता दे की भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को की थी। सरकार ने देश में सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर लगाना जरूरी कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यह एक तरह के नंबर प्लेट होती है जिसे भारत सरकार ने तय किए गए मानक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया है यह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अल्युमिनियम से बनी होती है और इसमें कई तरह के सिक्योरिटी फीचर होते हैं।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह एचएसआरपी है निर्देशों का पालन नहीं करने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियम के अनुसार जुर्माना किया जाएगा मोटर या अधिनियम 1988 में दिए गए प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनल्टी से बचने के लिए केंद्रीय वाटर या नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह एचएसआरपी समान दिखने वाली प्लेट स्मार्ट नंबर प्लेट कैसे होलोग्राम इंडिया मार्क इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाली वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण सिद्ध प्लेट से बदलना अनिवार्य कर दिया है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल एसोसियेशन (फाडा) एवं रायपुर ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसियेशन (राडा) समय समय पे अपने डीलरी को सरकार के द्वारा उठाये गये कदमो से अवगत करते आया है इसी क्रम में केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर यान 1989 के प्रावधानों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन व् दिशा निर्देशों के तहत इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिससे डीलरो व् वाहन मालिको को असुविधा का सामना ना करना पड़े और कार्य की सुगमता से किया जा सके। इस संगोष्ठी में परिवहन विभाग के सेक्रेटरी एस प्रकाश विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के मनीषराज सिंघानिया व विवेक गर्ग के अतिरिक्त रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (राडा) के उपाध्यक्ष कैलाश खेमानी एवं सभी वरिष्ठ सदस्य, अनिल अग्रवाल, शशांक शाह, जयेश पिथालिया, नीरज अग्रवाल सहित प्रदेश के अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलर और उनके कर्मचारी शामिल थे।

निगम आयुक्त अनिबनाश मिश्रा ने बड़े बकायादारों से बकाया राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाने दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने निगम के बड़े बकायादारों से बकाया राजस्व वसूली हेतु अभियान चलाने के दिए निर्देश रायपुर । आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में साप्ताहिक टीएल बैठक में कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए. आयुक्त ने निगम हित में निगम के बड़े बकायादारों से बकाया राजस्व वसूली करने अभियान चलाने के निर्देश दिये।

आयुक्त ने सफ़ाई, पेयजल, सड़क बत्ती से सम्बंधित कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं. आयुक्त ने अधिकारियों को नवीन विकासकार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण की सूची तैयार करने निर्देशित किया है। आयुक्त ने विकास कार्यों में समयसीमा एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं. आयुक्त ने जोन कमिश्नरों को प्रतिदिन सतत मॉनिटरिंग कर रायपुर शहर की सफ़ाई व्यवस्था को राजधानी के अनुरूप बनाने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारियों को पुख्ता तौर पर करवाना सुनिश्चित करने निर्देशित किया है।

नया रायपुर से मंदिर हसौद तक शीघ्र पटरियों पर दौड़ेगी मेमू

रायपुर। नया रायपुर से मंदिर हसौद के बीच मंगलवार की शाम को रेलवे द्वारा एमप्टी मेमू रैक (खाली ट्रेन) का ट्रायल रन किया गया, जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि नया रायपुर और मंदिर हसौद के मध्य जल्द ही मेमू ट्रैक पर दौड़ने लगेगी और आगे सब कुछ योजनाबद्ध हुआ तो मेमू को रायपुर रेलवे स्टेशन तक भी लाया जा सकता हैं। हालांकि इस बात की अधिकारिक तौर पर रेलवे की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। उल्लेखनीय हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर में बने सीबीडी स्टेशन का उद्घाटन नवंबर में किया है। उद्घाटन के बाद आवश्यक उपकरणों और सुविधाओं से सीबीडी को लैस करने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है जिससे संकेत हैं कि अगले सप्ताह तक नया रायपुर से मंदिर हसौद के बीच मेमू ट्रेन दौड़नी शुरु हो जाएगी।

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने CGPSC में सफलता प्राप्त करने वाली छात्राओं का सम्मान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की छत्तीसगढ़ इकाई ने अपनी प्रदेश प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में सीजीपीएससी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का सम्मान किया। बैठक ठाकुर विघ्नहरण सिंह भवन, सरोना में आयोजित की गई, जिसमें समाज और शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले कई लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुंगेली जिले की लोरमी निवासी किरण राजपूत, जिन्होंने सीजीपीएससी परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया, और महासमुंद जिले की नंदनी साहू, जिन्होंने पांचवां स्थान प्राप्त किया, को सम्मानित किया गया। दोनों छात्राओं को पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम सहित अन्य सदस्यों ने उनकी सफ्लता को मेहनत और संस्कारों का परिणाम बताया।

प्रदेश अध्यक्ष अवधेश गौतम ने छत्तीसगढ़ में महासभा की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बेटियों की इस सफ्लता से समाज को प्रेरणा मिली है। साथ ही, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि क्षत्रिय समाज अपने अधिकारों और सम्मान के लिए हमेशा सजग रहेगा। बैठक में क्षत्रिय समाज की राजनीति में घटती भागीदारी पर चिंता जताई गई। महासभा के महामंत्री मनहरण सिंह ने प्रस्ताव रखा कि राजनीतिक दलों को क्षत्रिय जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान देना चाहिए। प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया और इसे सरकार के ध्यानाकर्षण हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में वक्ताओं ने आरक्षण की वजह से योग्य उम्मीदवारों के हनन पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने यह भी कहा कि समाज को अब संगठित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। कार्यक्रम में राधवेंद्र सिंह राजू, सुखबीर सिंह भदौरिया, पारस सिंह चौहान, एस.के. सिंह, और रविंद्र सिंह सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों से क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। आभार प्रदर्शन राष्ट्रीय महामंत्री रविंद्र सिंह ने किया।

दिव्यांग बच्चों को किया श्रवण यंत्र वितरित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर नगर निगम के सभापति और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने अपने जन्मदिन के अवसर पर न केवल समाज सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि रायपुर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों की शुरुआत भी की। अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में श्री दुबे ने दिव्यांग बच्चों के बीच श्रवण यंत्र वितरित किए। यह यंत्र बच्चों की सुनने की क्षमता में सुधार लाने के लिए दिए गए थे, जिससे उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित कंबल व गरम कपड़ों के वितरण कार्यक्रम में भी भाग लिया।

श्री दुबे ने अपने वार्ड में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इनमें सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, शौचालय निर्माण और बुनियादी सुविधाओं का समावेश था। उन्होंने इन कार्यों की शुरुआत करते हुए स्थानीय निवासियों से कहा कि उनके द्वारा किए गए ये विकास कार्य शहर के हर एक नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होंगे।

शहर के 10 वार्डों में जाकर वहां के निवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और वार्डवासियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री दुबे ने मैनपाट दुर्घटना में चंगोराभाटा के 4 युवकों की असमय मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया।

श्री दुबे ने यह भी कहा कि रायपुर के विकास के लिए उनका संकल्प सशक्त है। उन्होंने महापौर के कार्यकाल के दौरान शहर के समग्र विकास के लिए कड़ी मेहनत की और आगे भी यह कार्य जारी रखने का वादा किया। उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया जाएगा, ताकि हर वर्ग के नागरिक को लाभ मिले।

श्री दुबे की यह पहल न केवल उनके नेतृत्व की गुणवत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वे समाज के हर तबके की भलाई के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उनके कार्यों से रायपुर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, और यह शहर के लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर बढने् का संकेत है।

बॉसी लुक में करिश्मा तन्ना ने बरपाया कहर, कैमरे के सामने एक्ट्रेस ने दिए सिजलिंग पोज

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना हमेशा अपनी खूबसूरती और फैशन स्टेटमेंट्स के कारण सोशस मीडिया पर लाइमलाइट बटौरती रहती हैं। उनका कातिलाना अवतार इंटरनेट पर आते ही बवाल मचाने लगता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें फैंस के बीच साझा की हैं। इन फोटोज में उनका स्टनिंग अवतार देखकर फैंस एक बार फिर से बेकाबू हो गए हैं।

एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से अक्सर सोशल मीडिया फैंस का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। उनका कातिलाना अंदाज इंटरनेट पर आते ही छा जाता है।

अब हाल ही में एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। इन फोटोज में उनका स्टनिंग लुक देखकर फैंस दीवाने हो गए हैं।

करिश्मा तन्ना जब भी अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं तो फैंस उनके लुक पर लाइक्स और कॉमेंट्स करते नहीं थकते हैं।

इन फोटोज में आप देख सकते हैं करिश्मा तन्ना ने बेहद ही शानदार बेज लुक में कोट और शॉर्ट्स पहना हुआ है, एक्ट्रेस अपने इस लुक में बेहद ही शानदार नजर आ रही हैं। खुले बालों को मैसी लुक देकर और लाइट मेकअप कर के एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने अपने आउटलुक को बेहद ही शानदार तरीके से निखारा है।

बता दें कि एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने नए-नए लुक्स में फोटोज पोस्ट करती रहती हैं।

भूल भुलैया 4 में होगी अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की एंट्री?

कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है और यह पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म में अक्षय कुमार नजर आए थे और दूसरे भाग में कार्तिक ने उनकी जगह ली।हाल ही में निर्देशन अनीस बज्मी ने बताया था कि इस फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त बन रही है। अब खबर है कि भूल भुलैया 4 में अक्षय की एंट्री हो सकती है।

भूषण कुमार ने बताया

रिपोर्ट्स के अनुसार, भूल भुलैया 4 में अक्षय भी नजर आ सकते हैं। साथ ही दूसरी किस्त में नजर आई कियारा आडवाणी भी चौथी किस्त की स्टार कास्ट में शामिल होंगी। निर्माता भूषण कुमार ने भी इसके कुछ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, सबकुछ कहानी पर निर्भर करता है। सभी को एक साथ लाना तभी सार्थक होगा, जब कोई ठोस कहानी हो। भूषण ने अक्षय की मौजूदगी की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया।

भूल भुलैया 3 में कार्तिक की जोड़ी तृप्ति डिमरी के साथ बनी है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।

बता दें कि भूल भुलैया 3 2007 में आई फिल्म भूल भुलैया का तीसरा भाग है। इस फिल्म का सीक्वल 2022 में आया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुआ।

अभिनेत्री आलिया भट्ट करेंगी हॉरर फिल्म चामुंडा, स्त्री 2 के मेकर्स से चल रही बात

बॉलीवुड को 'स्त्री 2' जैसी ब्लॉकस्टर फिल्म देने वाले दिनेश विजान बहुत जल्द बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने वाले हैं। जल्द ही दिनेश एक नई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म लेकर आ रहे हैं। जिसका नाम चामुंडा है। खबरें हैं कि दिनेश की इस फिल्म में श्रद्धा कपूर नहीं बल्कि आलिया भट्ट सबको डराने वाली हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट इस वक्त दिनेश विजान की फिल्म 'चामुंडा' के लिए उनके चर्चा कर रही हैं। वहीं मेकर्स भी आलिया पर बड़ा दांव लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में आलिया को कई बार मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस में भी स्पॉट किया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार आलिया को दिनेश विजान की ये सुपरनैचुरनल थ्रिलर फिल्म काफी पसंद आई है। एक्ट्रेस अगले साल फिल्म को साइन भी कर सकती हैं।

जानकारी की अनुसार इस फिल्म में पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी नजर आने वाली थी। उस वक्त फिल्म का टाइटल देवी बताया जा रहा था। लेकिन अब इसे बदलकर 'चामुंडा' कर दिया गया है। बता दें दिनेश विजान की 'स्त्री 2' ने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। जिसमें श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और तमन्ना भाटिया जैसे स्टार्स नजर आए थे।

वहीं बात करें आलिया भट्ट के वर्कफ्रंट की तो एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म 'जिगरा' में नजर आई थी। जिसमें उनके साथ वेदांग रैना भी अहम किरदार में थे। उन्होंने एक्ट्रेस के भाई का रोल निभाया था। वहीं इसके अलावा आलिया की पाइपलाइन में 'अल्फा' भी है। जिसमें वो शरवरी वाघ के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी।

बता दें कि आलिया भट्ट अपने बिजी शेड्यूल के बीच फैमिली पर भी पूरी ध्यान दे रही हैं। हाल ही में वो अपने पति रणबीर कपूर और बेटी राहा कपूर के साथ मैच देखने स्टेडियम पहुंची थी। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं।

सूखी खांसी से पाना चाहते हैं छुटकारा?

सूखी खांसी एक आम समस्या है, जो कई कारणों से हो सकती है। मुल्लेन तेल एक ऐसा एसेंशियल ऑयल है, जो सूखी खांसी को कम करने में मदद कर सकता है।यह तेल मुल्लेन पौधे के पत्तों और फूलों से निकाला जाता है और इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और बैक्टीरिया हटाने वाले गुण होते हैं।इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे मुल्लेन तेल का उपयोग करके आप सूखी खांसी से राहत पा सकते हैं।

मुल्लेन तेल की भाप लें

मुल्लेन तेल की भाप लेना सूखी खांसी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें कुछ बूंदें मुल्लेन तेल की डालें। अब सिर पर तौलिया डालकर इस भाप को गहरी सांस लेते हुए अंदर लें। इससे आपके गले और श्वसन तंत्र को आराम मिलेगा, बलगम ढीला होगा और सूखी खांसी कम होगी।यह प्रक्रिया दिन में 2 से 3 बार करें ताकि आपको जल्दी राहत मिल सके।

चाय में मिलाएं

मुल्लेन तेल का सेवन चाय के रूप में भी किया जा सकता है।इसके लिए एक कप गर्म पानी में कुछ बूंदें मुल्लेन तेल की मिलाएं और इसे धीरे-धीरे पिएं।यह चाय आपके गले को नमी प्रदान करेगी, सूजन कम करेगी और गले की खराश को ठीक करेगी। इससे आपकी सूखी खांसी में राहत मिलेगी और आप बेहतर महसूस करेंगे।इस चाय को दिन में 2-3 बार पीने से जल्दी आराम मिलेगा।

छाती पर मालिश करें

मुल्लेन तेल का उपयोग छाती पर मालिश करने के लिए भी किया जा सकता है।इसके लिए थोड़ी मात्रा में मुल्लेन तेल लेकर अपनी छाती पर हल्के हाथों से मालिश करें।इससे आपके श्वसन तंत्र को आराम मिलेगा और बलगम निकलने में मदद मिलेगी, जिससे आपकी सूखी खांसी कम होगी। इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार दोहराएं ताकि आपको जल्दी राहत मिल सके और आपकी खांसी में सुधार हो।

ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें

ह्यूमिडिफायर का उपयोग करके आप अपने कमरे की हवा को नम बना सकते हैं, जिससे आपका गला सुखा नहीं रहेगा और आपको राहत मिलेगी।ह्यूमिडिफायर के पानी में कुछ बूंदें मुल्लेन तेल की डाल दें ताकि उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैले और आपको सांस लेने में आसानी हो।यह उपाय न केवल आपके गले को आराम देगा बल्कि श्वसन तंत्र को भी साफ रखेगा, जिससे सूखी खांसी कम होगी। इस प्रक्रिया को रात में सोते समय अपनाएं।

गरारे करें

गरारे करना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिसमें आप गर्म पानी में थोड़ी सी नमक मिलाकर गरारे कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो 1-2 बूँदें मुल्लेन तेल मिला सकते हैं।इससे आपके गले में जमा कफ निकल जाएगा और गले की सूजन कम होगी। यह प्रक्रिया दिन में 2-3 बार करने से आपको जल्दी राहत मिलेगी और सूखी खांसी में आराम मिलेगा।

विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म जीरो से रीस्टार्ट की रिलीज तारीख से उठा पर्दा

फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म जीरो से रीस्टार्ट का एक आकर्षक डिजिटल मोशन पोस्टर जारी किया। जिसमें सिनेमाई दुनिया की शानदार झलक है।

डिजिटल मोशन पोस्टर आउट

डिजिटल मोशन पोस्टर में आकर्षक शीर्षक भी नजर आ रहा है। दर्शक फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। पोस्टर को साझा कर विधु विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने कैप्शन में लिखा 'आपने 12वीं फेल देखी और उसे पसंद किया, अब जानिए कि यह फिल्म कैसे कभी बन ही नहीं पाई और एक दृढ़ निश्चयी फिल्म निर्माता जिसने कभी हार नहीं मानी! विधु विनोद चोपड़ा प्रस्तुत करते हैं, जीरो से रीस्टार्ट।

इसके साथ विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने कैप्शन के साथ लिखा जीरो से रीस्टार्ट। 13 दिसंबर को सिनेमाघरों में। बता दें कि जीरो से स्टार्ट एक नई अवधारणा है। जीरो से रीस्टार्ट कहानी कहने की परंपराओं के दौरान आ रही चुनौतियों को दिखाती है।

फिल्म के बारे में विधु विनोद ने कहा मेरे लिए यह ड्रॉइंग बोर्ड पर वापस जाने और शून्य से शुरू करने जैसा है। मैं इस कहानी को उन सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, जिन्होंने कभी अपने जीवन में बाधाओं का सामना किया है। मैं उन्हें कभी हार न मानने और प्रयास करते रहने के लिए कहना चाहता हूं। जैसा कि हम कहते हैं लगे रहो!

जीरो से रीस्टार्ट एक प्रेरणादायक कहानी का वादा करती है, जो नए सिरे से शुरुआत करने की यात्रा को दिखाती है। विधु विनोद चोपड़ा ने हाल ही में आयोजित आईफा 2024 में अपनी फिल्म जीरो से रीस्टार्ट के शीर्षक की घोषणा की थी। निर्देशक ने पहले कहा था कि यह फिल्म विक्रांत मैसी की 12वीं फेल का प्रीक्वल है। जीरो से रीस्टार्ट 13 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

इस बीच पेशेवर काम की बात करें तो विधु विनोद चोपड़ा की झोली में जीरो से रीस्टार्ट समेत कई फिल्में हैं। चोपड़ा को चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। चोपड़ा को क्राइम ड्रामा परिंदा, देशभक्ति रोमांटिक ड्रामा 1942 ए लव स्टोरी और मिशन कश्मीर जैसी उल्लेखनीय फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है।

इसके अतिरिक्त, उन्हें मुन्ना भाई फिल्म सीरीज के साथ 3 इडियट्स, पीके और संजू के निर्माण के लिए भी सराहा जाता है। उनका आखिरी निर्देशन प्रयास 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रहा। यह बायोग्राफिकल ड्रामा मनोज कुमार शर्मा की कहानी है।

गले की खराश के लिए नमक के पानी से गरारे करना अच्छा इलाज है?

गले की खराश एक आम समस्या है, जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। इस समस्या से राहत पाने के लिए कई घरेलू उपाय अपनाए जाते हैं, जिनमें से एक है नमक पानी से गरारे करना। यह उपाय प्राचीन काल से ही प्रचलित है और माना जाता है कि इससे गले की सूजन कम होती है और आराम मिलता है। यह वास्तव में प्रभावी है? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

नमक के पानी के फायदे

नमक के पानी का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। यह माना जाता है कि नमक में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने में मदद कर सकते हैं।इसके अलावा गरारे करने से गले की सूजन कम होती है और आराम मिलता है। हालांकि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके प्रभाव सीमित होते हैं और यह केवल अस्थायी राहत प्रदान करता है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण

वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, नमक के पानी से गरारे करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि यह गले की खराश को पूरी तरह ठीक कर सकता है।कुछ शोध बताते हैं कि इससे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन इसे इलाज का स्थायी तरीका नहीं माना जा सकता। इसलिए इसे केवल सहायक उपाय के रूप में ही देखा जाना चाहिए और इसके साथ अन्य उपचार विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए।

अन्य उपचार विकल्प

गले की खराश के लिए अन्य कई उपचार विकल्प भी उपलब्ध हैं जैसे कि गर्म चाय या शहद का सेवन करना, अदरक और तुलसी का काढ़ा पीना आदि। ये सभी उपाय भी अस्थायी राहत प्रदान करते हैं। इनका उपयोग डॉक्टर द्वारा सुझाए गए दवाओं के साथ ही करना चाहिए ताकि समस्या जड़ से खत्म हो सके और लंबे समय तक राहत मिल सके। घरेलू उपायों पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं होता है।

डॉक्टर की सलाह जरूरी

अगर गले की खराश लंबे समय तक बनी रहती है या बार-बार होती है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। घरेलू उपायों पर निर्भर रहना सही नहीं होता क्योंकि इससे समस्या बढ़ सकती है और गंभीर रूप ले सकती है।नमक के पानी से गरारे करना एक पुराना घरेलू उपाय हो सकता है, लेकिन इसे इलाज का स्थायी तरीका मानना गलत होगा। बेहतर होगा कि आप डॉक्टर की सलाह लें और उचित उपचार करें।

सरगुन मेहता व रवि दुबे ने लॉन्च किया अपना पारिवारिक मनोरंजन प्लेटफॉर्म

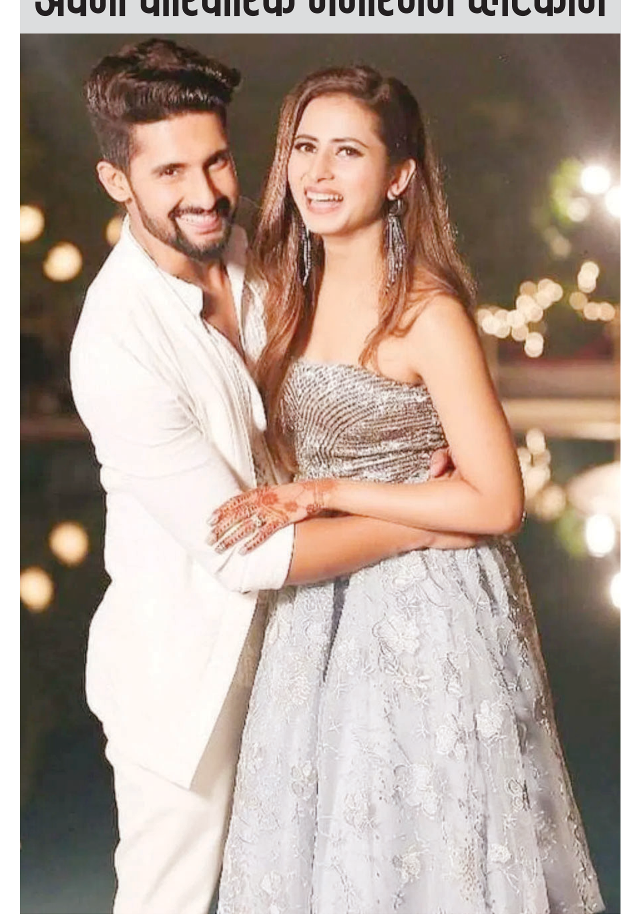

अभिनेता रवि दुबे और अभिनेत्री सरगुन मेहता की जोड़ी छोटे पर्दे की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है। सोशल मीडिया पर अक्सर दोनों साथ में तस्वीरें साझा करते रहते हैं। प्रशंसक सरगुन और रवि को साथ में देखना भी काफी पसंद करते हैं। अब सरगुन और रवि ने अपना खुद का पारिवारिक मनोरंजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम ड्रीमियाता ड्रामा रखा गया है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर इस खबर का ऐलान किया है।

सरगुन और रवि ने वीडियो साझा करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, हमारा सपना अब आपका है। आपके पूरे परिवार के लिए एक नया मनोरंजन प्लेटफॉर्म ड्रीमियाता ड्रामा जल्द ही आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए बने रहें। सरगुन और रवि ने साथ में टीवी शो उडारियां का निर्माण भी किया है, जो बहुत लोकप्रिय हुआ।बता दें सरगुन और रवि ने 2013 में शादी रचाई थी। दोनों की पहली मुलाकात 12/24 करोल बाग के सेट पर हुई थी।

जिले में जल एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु किए जा रहे कार्य सराहनीय-राज्यपाल रमेन डेका

राज्यपाल डेका कलेक्टोरेट में अधिकारियों से चर्चा कर योजनाओं के क्रियान्वयन से हुए अवगत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका धमतरी जिले के प्रवास पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों से बैठक लेकर शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा की। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। बैठक में राज्यपाल श्री डेका ने जिले में जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली।

इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आमजनों को जल संरक्षण की दिशा में जोड़ने एवं उन्हें जागरूक करने संबंधी तैयार किए गए लघु फिल्म को राज्यपाल श्री डेका के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि जिले में जल एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए पूरा जिला प्रशासन बधाई के पात्र हैं। राज्यपाल श्री डेका ने जिले में ''एक पेड़ मां के नाम'' के तहत लगाए गए पौधों की जानकारी ली और कहा कि लगाए गए पौधों को जीवित रखने लोगों को जागरूक करें। इसके साथ ही पौधों को संरक्षित रखें और

इसकी जानकारी भी संधारित करें।

राज्यपाल ने जिले में टी.बी.उन्मूलन के तहत चलाए गए कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने जिले में टी.बी.के कुल जांच, पॉजिटिव मरीजों की संख्या, निक्षय पोषण योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही, निक्षय मित्र पंजीयन आदि के बारे में पूछा। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि जिले के 10 टी.बी.मरीजों को निक्षय मित्र बन वे सहयोग प्रदाय करेंगे। इसमें रेडक्रॉस को भी जोड़ने की बात उन्होंने कही। राज्यपाल श्री डेका ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी आवासों को गुणवत्ता व समय का ध्यान रखते हुए पूरा करावें। साथ ही हितग्राही से संबंधित जानकारी की सूचना प्रदर्शित की जाए। राज्यपाल श्री डेका ने एनसीसी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि बच्चों को एनसीसी के प्रति प्रोत्साहित करें। एनसीसी से बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास होता है।

बैठक में राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि लोगों को हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाए जाने हेतु जागरूक करें। उन्होंने जैविक कृषि को बढ़ावा, स्वच्छता, बाल लिंगानुपात के प्रति जागरूकता, लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करने, बच्चों की शिक्षा, विशेषकर श्रमिक एवं अनाथ बच्चों की शिक्षा, जिले में पुस्तकालय एवं वाचनालय, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण एवं राष्ट्र के महापुरूषों के प्रति सम्मान का भाव, असहाय, परित्यक्त वृद्धजनों की सहायता, भिक्षुकों को धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के जरिए मदद करना, ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के कौशल का उपयोग कर उनकी आय बढ़ाना, स्व सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी, नशा से ग्रसित लोगों के लिए सुधारात्मक उपाय, जनजातीय एवं वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं का विकास तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने के उपाय इत्यादि के बारे में विस्तृत चर्चा भी की। दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूह को बेहतर सुविधाएं मिले। जैविक खेती पर जोर देते हुए। किसानों को सब्जियां उत्पादन के लिए प्रेरित करें, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित और बाजार मूल्य मिले। बैठक में धमतरी जिले की कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी, जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ के 100 रेशम कृमिपालक किसानों ने महाराष्ट्र के वर्धा में लिया प्रशिक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य सरकार प्रदेश के रेशम किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं निरंतर उन्नति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश के 100 रेशम किसानों का अध्ययन दल महाराष्ट्र के वर्धा में स्थापित रेशम कृषि की उन्नत तकनीक का अध्ययन किया। इन रेशम किसानों को मिट्टी, पौधे, कृमिपालन, कृमिपालन हेतु उपकरण, सिंचाई आदि सहित तकनीकी बारीकियों का प्रशिक्षण दिया गया।

छत्तीसगढ़ के किसान महाराष्ट्र के वर्धा में प्रशिक्षण पश्चात् काफी प्रसन्न मुद्रा में कहा कि वे वर्धा आकर रेशम कृषि पालन के माध्यम से कम समय में अधिक आमदनी प्राप्त करने का गुर सीख लिया है। अब वे छत्तीसगढ़ में भी इन नवीन तकनीकों का प्रयोग कर कृमिपालन व ककून तैयार करेंगे, जिससे उच्च क्वालिटी की सिल्क तैयार कर बाजार में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा सिल्क समग्र योजना के रेशम विस्तार के लिए कृषकों का चयन कर उन्हें महाराष्ट्र के वर्धा अध्ययन भ्रमण के लिए भेजा गया था। सिल्क समग्र योजना केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। रेशम किसान मात्र 26 दिनों में ही 66 हजार से एक लाख तक की आय अर्जित कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के चयनित कृषकों को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में सिल्क समग्र से लाभ लेकर उत्पादन कर अधिक आय अर्जित करने वाले कृषकों के कार्यों का अवलोकन कराया गया।

इस दौरान कृषकों से चर्चा, उनके द्वारा किये जा रहे प्रगतिशील कार्य, तकनीकी कार्यों हेतु व्यवस्था की जानकारी मिली। इसी प्रकार रेशमकीट पालन के कार्यों हेतु सावधानियां, वैज्ञानिक उपाय, उत्पादन, बाजार व्यवस्था, भुगतान की प्रक्रिया, राशि की प्राप्ति तथा आगामी वर्षों के लिए कार्य योजनाएं एवं इस कार्य में महिलाओं की सहभागिता, आय अर्जन इत्यादि समस्त विषयों पर चर्चाएं की गई।

देखते ही देखते सपनों का आशियाना पूरा होकर तैयार हो गयाः जमुना बैगा

श्रीकंचनपथ न्यूज

एमसीबी। पीएम जनमन योजना अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले ग्राम देवगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के हितग्राही जमुना बैगा के खुद के पक्के आशियाने का सपना साकार हुआ है। हितग्राही ने आवास पूर्ण होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना ने उनकी दशा और दिशा बदल दी है।

योजना के तहत वर्ष 2023-24 में उन्हें आवास की मंजूरी मिली। पंचायत स्तर पर दस्तावेजों की पूर्ति होने के साथ ही आवास निर्माण प्रारंभ किया गया। जिसमें पहली किश्त के रूप में 40 हजार रुपये मिलते ही उनकी मकान निर्माण की उम्मीद पक्की होने लगी। उनके द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर आवास निर्माण कार्य शुरू किया गया। मकान निर्माण आगे बढ़ने के साथ ही प्रगति के आधार पर किश्त की राशि मिलती गई और देखते ही देखते उनके सपनों का आशियाना पूरा होकर तैयार हो गया।

हितग्राही अपने पुराने दिनों की कठिनाई याद करते हुए बताते हैं कि वह एक खेतीहर मजदूर हैं। रोजी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। आवास निर्माण से उनका परिवार कच्ची झोपड़ीनुमा घर में निवास करते थे। जहां जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन था। मौसम के अनुसार अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकना, दीवारों में सीलन आना, साथ ही सर्दी के समय रात में ठण्ड के कारण नींद नहीं आती थी। साथ ही साल भर जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू इत्यादि का डर बना रहता था। अब पक्का मकान मिलने से उनकी ये समस्याएं दूर हो गई हैं। अब वे अपने परिवार के साथ पक्के आवास में चैन की नींद सो रहे हैं। पक्की छत वाली घर होने से उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। नए आवास में परिवार के साथ हंसी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को अपने आर्थिक एवं सामाजिक वृद्धि हेतु आभार व्यक्त करते हुए विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय का सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया।

निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए आयोग कटिबद्ध : अजय सिंह

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत कांकेर के सभाकक्ष में सुबह 11.00 बजे से नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में आगामी आम/उप निर्वाचन अंतर्गत निर्वाचन कार्यों की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में बस्तर संभाग के संभाग आयुक्त श्री डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी., पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी श्री ओ.पी. पाल, आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे सहित संभाग के सभी जिला के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए।

इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी अधिकारियों को बस्तर संभाग में पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में प्रति एक हजार मतदाता के लिए एक मतदान केन्द्र और पंचायतों में निर्वाचन के लिए प्रति 500 मतदाता हेतु एक मतदान केन्द्र बनाया जाय । साथ ही यह भी कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम

निर्वाचक नामावली में अनिवार्य रूप से जोड़े जाएं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक में मुख्य रूप से चुनाव के सुचारू रूप से संचालन हेतु चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केन्द्रों की स्थिति और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण तैयारियों की समीक्षा की ।

इस बैठक के माध्यम से चुनाव के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग के साथ ही प्रदेश के सभी संभागों में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा सम्पन्न हो गई है। आगामी समय में चुनाव की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ आयोग की संयुक्त रूप से बैठक की जाएगी, जिसके तहत चुनावी प्रक्रिया के दौरान होने वाली चुनौतियों और संभावित समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी । उन्होंने अधिकारियों को चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि 01 अक्टूबर 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पात्र लोगों के नाम निर्वाचक नामावली में अनिवार्य रूप से होने चाहिए।

इस दौरान बैठक में बस्तर संभागायुक्त श्री सिंह ने संभाग के सभी जिलों में की जा रही निर्वाचन की तैयारियों की संक्षिप्त जानकारी दी। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर संभाग श्री सुंदरराज ने निर्वाचन के दौरान की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था के संबंध जानकारी दी। साथ ही संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने-अपने जिलों के निर्वाचन संबंधी तैयारियों की अद्यतन स्थिति से आयोग को अवगत कराया।

ने सुरक्षा उपायों और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, कर्मचारियों की तैनाती, और निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता की भी समीक्षा की ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग बना रहे ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।

नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा : उद्योग मंत्री

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर आधारित निर्यात प्रोत्साहन एवं निवेश हेतु स्टेकहोल्डर कनेक्ट कार्यशाला का शुभारंभ किया। नीति आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार संजीत कुमार, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, संचालक उद्योग प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेस कुमार सहित उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि हम सब राज्य के औद्योगिक विकास एवं राज्य से निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से

आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा एवं विचार-विमर्श के लिए यहां एकत्रित हुए है। प्रदेश में नवीन उद्योग नीति 2024-2030 जो एक नवंबर से लागू हो चुकी है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार की मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग कैसे स्थापित हो इसे ध्यान में रखकर यह उद्योग नीति तैयार की गई है। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में आयोजित केबिनेट बैठक में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।

इस नीति में ज्यादा से ज्यादा अनुदान सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हो इसमें प्रावधान किए गए है। उद्योग धंधे स्थापित होने से प्रदेश का विकास होगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्यामियों की सुविधा के लिए प्रदेश में सिंगल विंडो प्रणाली लागू किया गया है। प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित होने से प्रदेश का तेजी से विकास होगा। श्री देवांगन ने कहा कि उद्योगों के साथ-साथ इससे अप्रत्यक्ष रूप से हजारो लोगों को भी रोजगार मिलेगा।

नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार संजीत सिंह ने कहा कि कार्यशाला के आयोजन के लिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति अन्य राज्यों के लिए उदाहरण साबित होगी। सिंगल विंडो प्रणाली से उद्यामियों को सहुलियत होगी। उन्होंने कार्यशाला के आयोजन के लिए अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री सिंह ने आश्वस्त किया कि नीति आयोग की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। सचिव उद्योग रजत कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से ब्याज अनुदान, राज्य लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छुट, विद्युत शुल्क छुट, प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान के प्रावधान किए गए है। सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेस कुमार ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला के दौरान सवाल-जवाब के दौरान जिज्ञासा का समाधान किया गया।

अस्पताल पहुंचकर मरीजों का पूछा हाल चाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा आज सुबह राजधानी रायपुर स्थित एम्स, डी के एस और मेकाहारा हॉस्पिटल पहुँचे। इस दौरान मंत्री श्री वर्मा ने अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ-साथ मरीज़ों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री वर्मा ने अस्पताल की व्यवस्था और इलाज के संबंध में मरीजों से जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान अस्पताल के उपस्थित चिकित्सकों को समय पर मरीज़ों को बेहतर इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस दौरान मंत्री वर्मा ने बालौदाबाज़ार जिले के ग्राम रवान के रहने वाले पुकार यादव, ग्राम देवरी की निर्मला वर्मा, बालौदाबाज़ार के सुमन दास साहू से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी

ली।

सिर में चोट के इलाज के लिए डी के एस के वार्ड- सी 6 में भर्ती 20 वर्ष के श्री पुकार सिंह ने बेहतर इलाज के कारण स्वास्थ्य में तेजी से सुधार की जानकारी दी। इसी तरह नस में ब्लाकेज के इलाज के लिए मेकाहारा हॉस्पिटल के वार्ड-19 में भर्ती 55 वर्षीय श्री सुमन दास साहू ने स्वास्थ्य में सुधार की बात कही। इसी तरह बलौदाबाजार के ग्राम देवरी की 54 वर्षीय श्रीमती निर्मला वर्मा निमोनिया के इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है।

श्री वर्मा ने उनके स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सकों से चर्चा कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के लिए 10 दिसम्बर तक भेज सकते हैं अपनी प्रविष्टि

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा और जागरुकता के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के लिए मीडिया संस्थान 10 दिसम्बर तक अपनी प्रविष्टि आयोग के अशोका रोड, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड-2024 के तहत आयोग द्वारा चार श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें प्रिंट मीडिया और ऑनलाइन (इंटरनेट)/सोशल मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो के लिए दिए जाने वाले अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड के लिए चयनित मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आगामी 25 जनवरी 2025 को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष-2024 में मतदाता शिक्षा और जागरुकता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। लोगों को सुगम निर्वाचन के लिए जागरुक करने, निर्वाचन प्रक्रिया व निर्वाचन संबंधी आईटी एप्लीकेशन्स के बारे में शिक्षित करने, अनूठे या दूरस्थ मतदान केंद्रों की कहानियों तथा मतदान करने एवं मतदाता सूची में पंजीयन के लिए जागरुक करने जैसे कार्यों से निर्वाचन में सहभागिता बढ़ाने में मीडिया के उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के माध्यम से रेखांकित किया जाएगा।

खास खबर

जिलाबदर निगरानी बदमाश को छाती में घुमते पेट्रोलिंग पुलिस ने किया गिरफ्तार

धमतरी (ए.)। एक वर्ष के लिए जिला बदर किये जाने के बाद भी ग्राम छाती में खुलेआम घूम रहे बदमाश को कुरूद पेट्रोलियम पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

बता दें कि पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा गुंडा बदमाशों के उपर नजर रख कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये गए हैं। इसी तारतम्य में थाना कुरुद को मुखबिर से सुचना मिली की थाना कुरूद क्षेत्र का निगरानी बदमाश जिला बदर गिरधर बारले उर्फ बंटी पिता जीवन लाल बारले उम्र 28 साल साकीन छाती, बिना अनुमति के धमतरी जिला में प्रवेश कर अपने गांव छाती मंडी चौक के पास घूम रहा है,की सुचना पर बदमाश को घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया,बदमाश गिरधर बारले के पास धमतरी जिला में प्रवेश करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जो आरोपी को धारा 223(ए) बीएनए0 एवं छ.ग.जन सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। उक्त आरोपी को दिनांक 06/08/24 को जिला दंडाधिकारी धमतरी के द्वारा जिलाबदर की कार्यवाही की गई थी।

झुकने लगे हैं ओवर ब्रिज के खंभे : गंभीर हादसे का खतरा

रायपुर (ए.)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रिंग रोड क्रमांक -एक पर संतोषी नगर के पास निर्मित ओवर ब्रिज के दो खंभे तिरछे होकर खतरनाक ढंग से झुकने लगे हैं। इन्हें जिस चौकोर सीमेंटेड बॉक्स पर खड़ा किया गया है, वह भी उखड़ने लगा है। देखकर ऐसा लगता है कि अगर इन पिलरों को नहीं संभाला गया तो किसी भी समय कोई गंभीर जानलेवा हादसा हो सकता है लेकिन किसी का भी ध्यान इस खतरे की ओर नहीं जा रहा है। एक समाचार एजेंसी के संवाददाता ने उधर से आते समय अपने मोबाइल कैमरे से इसकी तस्वीर खींची। ये दोनों खंभे लोहे के बने गर्डर को भी थामे हुए हैं। इनके थोड़ा भी और खिसकने पर गर्डर भी गिर सकता है। यह ओवर ब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर है। मुम्बई से कोलकाता को जोड़ने वाले फोर लेन के इस राष्ट्रीय मार्ग पर दिन -रात लगातार विभिन्न प्रकार के मालवाहक वाहनों सहित हजारों वाहन गुजरते हैं। यात्री -बसें भी आती -जाती हैं। छत्तीसगढ़ के ही राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई की तरफ से और उधर ओड़िशा के सम्बलपुर,बरगढ़, खरियार रोड, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, सारंगढ़, सरायपाली, बसना, पिथौरा आदि शहरों से भी काफी संख्या में वाहनों का आना -जाना लगा रहता है। वहीं इस पुल के नीचे से भी हर दिन सुबह से देर रात तक राजधानी रायपुर के हजारों कामकाजी लोग कार, ऑटो रिक्शा और बाइक आदि वाहनों से आना -जाना करते हैं। दफ्तर और दुकान आदि आने - जाने वालों की संख्या सुबह और शाम को सबसे ज्यादा होती है।

अलग-अलग मामलों में 6 चोरियों का खुलासा दो नाबालिग सहित तीन आरोपी हुए गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। जामुल थाना क्षेत्र में चोरी के अलग अलग मामलों का खुलासा हुआ है। कुल 6 मामलों में पुलिस ने एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास ये चोरी का लोहा व नगदी रकम बरामद की गई है। आरोपियों ने 26 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच किराना दुकान सहित अन्य दुकानों के ताले तोड़े। इसके अलावा फैक्ट्री में भी सेंधमारी की थी।

मिली जानकारी के अनुसार जामुल थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। पिछले कुछ दिनों में ही आधा दर्जन वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने चोरी के मामलों को सुलझाने के लिए निर्देश दिया था। जामुल थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव पाण्डेय, एएसआई बेनी राम राजपूत, अजय सिंह, राजेश कुमार साहू, केसेन्द्र चौहान, ए. महफुज खान, इमानवेल खलखो एवं जामुल पेट्रोलिंग की संयुक्त टीम गठित कर उक्त अज्ञात आरोपियों को पकड़ने टीम लगाई गई।

मुखबिर सूचना पर संदेह के आधार पर आरोपी सुखिया कुर्रे उर्फ मलिंगा पिता स्व. भागचंद कुर्रे (30) गुरू घासीदास नगर तालाब के पास कुरूद रोड़ जामुल को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि 2 अन्य नबालिगों के उक्त चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। इसके अलावा दो अन्य आरोपी प्रदीप एवं हरीश कुमार सोनी उर्फ विक्की सोनी के साथ मिलकर फैक्ट्री के अंदर से लोहा की चोरी करने की बात भी बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 हजार रुपए का लोहा सिहत कुल 72 हजार रुपए का चोरी का सामान जब्त किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।

लाखों की चोरी करने वाले गैंती गैंग का पर्दाफाश तीन मुख्य आरोपी समेत 11 गिरफ्तार

रायपुर (ए.)। पुलिस ने लगातार लाखों रुपये की कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी के मामलों में संलिप्त गैंती गैंग का खुलासा किया है। इस गिरोह ने रायपुर के ग्रामीण इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के सुनसान मकानों को निशाना बनाते हुए 25 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। आरोपियों ने थाना मुजगहन, विधानसभा, तिल्दा नेवरा एवं मंदिर हसौद के आवासीय कॉलोनियों के सुने मकानों को निशाना बनाया था। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर अमरेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष सिंह के निर्देश पर 30 सदस्यीय एंटी क्राइम और साइबर यूनिट टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज, और मुखबिरों की मदद से आरोपियों को पकड़ा।

आरोपियों में प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर और बिलासपुर जिलों तक फैले हुए हैं। गिरोह द्वारा चोरी किए गए माल को गलाकर ज्वेलर्स को बेच दिया जाता था। कई किरायेदार मकानों के मालिकों द्वारा पुलिस को सूचना नहीं देने पर नोटिस जारी किया गया है। आरोपियों ने चोरी के लिए गैंती और पेचकस जैसे औजारों का इस्तेमाल किया। चोरी की घटनाओं से प्राप्त नकदी का उपयोग वाहन खरीदने में किया गया। सह-आरोपियों और ज्वेलर्स को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संगठित अपराध के तहत धाराओं में कार्रवाई की है साथ ही फाइनेंस कंपनियों को नोटिस देकर जांच तेज की गई।

चोरी के आरोपियों में सृजन शर्मा पिता प्रभु शर्मा उम्र 29 साल स्थाई पता मकान नंबर 54 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सरकंडा खमतराई बिलासपुर, उमेश उपाध्याय पिता स्व. वीरेंद्र उपाध्याय उम्र 26 वर्ष निवासी कालीमाई वार्ड हर्रीपारा जिला मुंगेली, सफीक मोहम्मद पिता नासिर मोहम्मद उम्र 25 वर्ष निवासी कालीमाई वार्ड हर्रीपारा जिला मुंगेली शामिल हैं। प्रकरण में संलिप्त माल खपाने वाले सहआरोपी में हर्ष कुमार बंजारे उर्फगोविंदा पिता शिव कुमार बंजारे उम्र 18 साल निवासी विनोबा भावे नगर जैतखाम थाना मुंगेली बिलासपुर। मोहम्मद आसिफसिद्दीकी पिता जावेद अहमद सिद्दीकी उम्र 40 सालनिवासी बशीर खान वार्ड पंडरिया रोड मुंगेली बिलासपुर। मेवा लाल कश्यप पिता दुर्गा प्रसाद कश्यप उम्र 43 सालनिवासी कपसिया कला थाना कोटा जिला बिलासपुर। हेमंत कश्यप पिता तुलसीराम कश्यप उम्र 33 साल निवासी परसा कांपा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर। कमलजीत कश्यप उर्फजीतू पिता स्व. दिनेश कश्यप उम्र 30 साल निवासी निकारबंद थाना तखतपुर जिला बिलासपुर शामिल हैं।

हाथियों के दल ने पहुंचाया फसलों को नुकसान

कोरबा (ए.)। वनमंडल कोरबा के करतला रेंज में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। यहां 50 सदस्यीय हाथियों का दल विचरण कर रहा है। यह दल दो दिनों तक पीडिया में एक साथ थे लेकिन बीती रात दल में से कुछ हाथी अलग होकर बोतली के जंगल में पहुंच गई है। हाथियों ने बोतली जाने से पहले पीडिया गांव में दो दर्जन से अधिक किसानों के धान की फसल को रौंद दिया। इतना ही नहीं एक ग्रामीण के झोपड़ी को भी तोड़ दिया है। हाथियों के द्वारा लगातार नुकसान पहुंचाए जाने से क्षेत्र के ग्रामीण काफी दुखी हैं क्योंकि खेतों में लगाया गया धान पककर तैयार हो गया है और किसान उसे काटकर धान खरीदी केंद्रों में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हाथियों द्वारा फसल को चैपट कर देने से उन्हें निराशा हाथ लग रही है।

बताया जाता है कि हाथियों का यह दल एक सप्ताह से क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं तथा प्रतिदिन खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीती रात कुछ हाथी बोतली गांव पहुंच गए लेकिन बड़ी संख्या में हाथी अभी भी पीडिया में मंडरा रहे हैं जिनके द्वारा फसल को नुकसान किए जाने की संभावना है। उधर पसरखेत रेंज में दो दिनों तक विचरण करने के बाद एक दर्जन हाथियों ने चचिया जंगल के कक्ष क्रमांक पी-1133 में दस्तक दे दी है।

हाथियों के अचानक आने से ग्रामीण दहशत में हैं। जहां कोरबा वनमंडल में हाथियों की दहशत बरकरार है वहीं कटघोरा वनमंडल में हाथियों की एक बार फिर वापसी हो गई है। कोरिया सीमा तक जाने के बाद वहां ग्रामीणों द्वारा खदेड़े जाने पर हाथियों का दल वापस पसान रेंज लौट गया है। बीती रात इस दल ने रेंज के सिर्री व समलाई नामक गांव में पहुंचकर पहले खेतों में रखे धान के करपे का भक्षण किया तत्पश्चात् खलिहानों में पहुंचकर धान की खरही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन ड्यूटी में तैनात वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने खदेड़ दिया जिससे वे वापस जंगल जाने को मजबूर हो गए।

रायपुर में बाघ का आहट शहरी क्षेत्र में मिले फुट मार्क

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर में बाघ की आहट से सनसनी फैल गई है। राजधानी के सेरीखेड़ी इलाके में बाघ दिखने की खबर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इलाके की एक मुकबधीर बालिका ने बाघ को देखा और इशारों में इसकी जानकारी दी। यही नहीं बाघ के फुट मार्कस भी देखे जाने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग इसकी जांच कर रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार तेलीबांधा थाना क्षेत्र के सेरीखेड़ी इलाके बाघ देखे जाने का दावा किया जा रहा है। मंगलवार की रात को सेवा निकेतन में रहने वाली एक मूखबधिर बालिका ने बाघ को देखा था। इसकी जानकारी उसने इशारों में वहां के इंचार्ज को दी। इसके बाद यह खबर तेजी फैल गई। सोशल मीडिया में बुधवार को सुबह से यह खबर वायरल हो रही है। वन विभाग की टीम को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वह अलर्ट हो गया।

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बाघ की आहट के कारण सेराखेड़ी के लोग दहशत में हैं और अपने घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। आसपास के किसान भी खेतों में जाने से बचते रहे। वन विभाग को फुट प्रिंटस मिले हैं और इसकी जांच की जा रही है। यह अफवाह है या फिर वास्तव में बाघ यहां देखा गया है इसकी जांच की जा रही है। यही नहीं शहरी इलाके में बाघ की आहट से वन विभाग भी हैरान है।

एसईसीएल खदान में हादसा, ड्रेसिंग के दौरान सिर पर गिरा कोयला, दो श्रमिकों की मौत

श्रीकंचनपथ न्यूज

मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ में एसईसीएल खदान हादसे में दो श्रमिकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खदान के अंदर ड्रेसिंग के दौरान ये घटना हुई है। सिर पर कोयला गिरने से दोनों श्रमिक घायल हुए थे। दोनों को उपचार के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल मनेन्द्रगढ़ लाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश सीमा से लगे मनेन्द्रगढ़ के राजनगर उपक्षेत्र के झिरिया अंडर ग्राउंड में ये हादसा हुआ है। घटना के बाद खदान में कार्यरत श्रमिकों में भय का माहौल है। मरने वाले श्रमिकों में लखन लाल और वॉल्टर तिर्की शामिल हैं। यह घटना खदानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के प्रति प्रबंधन की लापरवाही और खतरनाक परिस्थितियों को उजागर करती है। जिले के हसदेव क्षेत्र में एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) की झिरिया अंडरग्राउंड खदान में हुई यह दुर्घटना न केवल श्रमिक सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर करती है, बल्कि खनन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी उठाती है।

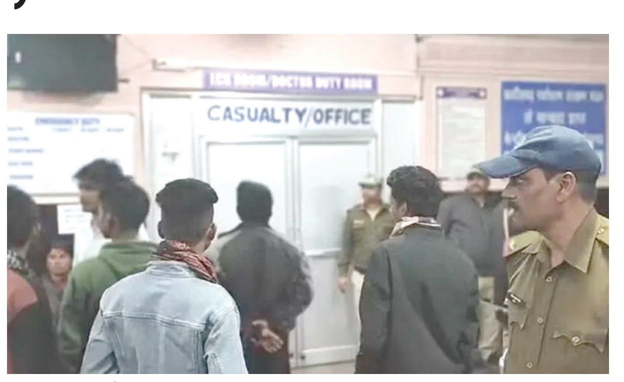

यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि खदान में सुरक्षा मानकों को गंभीरता से लागू नहीं किया जा रहा है। छत को सपोर्ट देने के लिए प्रयुक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस हादसे की तत्काल और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और दोषी प्रबंधन अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यह घटना सभी संबंधित पक्षों के लिए एक चेतावनी है कि खदान सुरक्षा को हल्के में लेना श्रमिकों की जान के लिए खतरा बन सकता है।

हाथी ने कमार बच्ची को पटक-पटककर मार डाला: धमतरी। नगरी ब्लॉक के रिसगांव आमाबहार में बीती रात करीब 11 बजे हाथी ने बच्ची को घर से उठाकर बाहर निकाला और पटक-पटककर मार डाला। बताया जाता हैं कि हाथी शावक है जो बीते दिनों पोटाश बम की चपेट में आकर घायल हुआ था, उसकी हालत चिंताजनक हुई, तो जंगल सफारी के डॉक्टरों ने इलाज किया।

नशे के कारोबारियों पर कसी नकेल, गुमशुदा लोगों की हुई घर वापसी

सूरजपुर। जिले के नए कप्तान प्रशांत ठाकुर के आने के बाद जहाँ नशे के कारोबारी पर लागतार कार्यवाही किया जा रहा है वही जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से एक माह में गुम हुए 26 लोगों को ढुंढा गया है। दो लोग जो पहले से गुम हुए थे उन्हें भी ढुंढा गया। पुलिस के द्वारा एक माह में 28 गुमशुदा लोगों को ढुंढ कर निकाला गया है। सूरजपुर जिले के भटगांव, प्रतापपुर, खड़गवां, झीलमीली, प्रेमनगर सहित अन्य थानों से नवंबर महीने में गुमशुदगी के 26 प्रकरण दर्ज हुए थे जिसमें 1 बालक, 3 बालिका, 8 पुरुष व 14 महिला गुम हुए थे, जिन्हें पुलिस ने एक माह में ढुंढते हुए कुल 28 लोगों को जिसमें दो लोग पुर्व में गुम हुए थे उन्हें भी ढुंढ निकाला है। नवंबर माह में पुलिस ने लगभग हर दिन एक लोगों को ढुंढा है। पुलिस ने जिस प्रकार से गुम हुए लोगों को उनके परिवार से मिलाया है उससे परिजनों के चेहरे में काफी खुशी देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस की इस काम की सभी सराहना कर रहे है।

दुल्हन बैंगल्स & फैंसी

RAKESH SINGH
Mob.-9840760388
7987759030

Specialist : Wedding mix match bangles, Glass bangle, Plastic bangle. Saree pin, Bindi, Rubber Band. Bracelet, Butter Fly, Ear ring and many more

पुष्पांजलि स्वीट्स के बाजू में, कृष्णा टाकिज रोड, रिसाली, भिलाई

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 26.11.2024

(ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना)

(प्रथम आमंत्रण)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन निविदायें प्रपत्र "अ" में प्रतिशत दर पर दिनांक 16.12.2024 तक आमंत्रित की जाती हैः-

निविदा आमंत्रण सू.क.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)
148/दुर्ग(दुर्ग)/2024	उपसंभाग क्रं. 01 दुर्ग के अंतर्गत विभिन्न आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत कार्य	78.72
150/दुर्ग(खैरागढ)/2024	सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल के योजनांतर्गत सर्राकापा से खौडा ढाबा तालाब मार्ग 2.00, सिंघोरी घोटवानी मार्ग लं. 3.70 कि.मी. एवं खैरागढ़ लॉजी मार्ग लं. 13.60 कि.मी. कुल लंबाई 19.30 कि.मी. में रोड फर्नीचर कार्य	44.70

टीप

1. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब portal एवं विभागीय वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in से डाऊनलोड की जा सकती है।
2. पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर एन.आई.टी. क्रमांक एवं कार्य का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जायें।

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मंडल दुर्ग

जी-242504327/4

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
सामान्य वनमण्डल दुर्ग

पुलगांव डिपो का ई-ऑक्सन का संक्षिप्त विज्ञापन

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दुर्ग वनमण्डल के अधिनस्थ शासकीय उपभोक्ता डिपो पुलगांव, अण्डा, पाटन, ऊतई, वन परिसर कुम्हारी, बेमेतरा एवं अन्य डिपो में संग्रहित ईमारती काष्ठ, जलाऊ एवं बल्ली का ई- ऑक्सन द्वारा निर्वर्तन निम्नानुसार किया जावेगा. इच्छुक बोलीदारों से अनुरोध है कि वे- ई- ऑक्सन में भाग लेवें. ई- ऑक्सन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय/संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है. ई- ऑक्सन में रखे जाने वाले अनुमानित मात्राः-

नीलाम तिथि - 12.12.2024
समय - प्रातः 9.00 बजे

नया ईमारती काष्ठ/जलाऊ चट्टा

परिक्षेत्र	डिपो	प्रजाति	लट्ठा घ.मी.	बल्ली नग	डेंगरी नग	जलाऊ चट्टा
दुर्ग	पुलगांव	सागौन लट्ठा/बल्ली, डेंगरी	42.286	8038	1893	-
बेमेतरा	बेमेतरा	सागौन लट्ठा	19.405	-	-	-
		योग:-	61.691	8038	1893	

अविक्रित काष्ठ/जलाऊ चट्टा

परिक्षेत्र	डिपो	प्रजाति	लट्ठा (घ.मी.)	चिरान घ.मी.	बल्ली/ डेंगरी नग	जलाऊ च.
दुर्ग	पुलगांव	सागौन लट्ठा/बल्ली/डेंगरी	272.251	-	2374/3014	-
-''-	-''-	मुण्डी/आम/मिश्रित लट्ठा	10.966	-	-	-
-''-	अण्डा	मिश्रित ल. ज./नीलगिरी लट्ठा	2.370	-	-	6
-''-	पाटन	सागौन लट्ठा, डे./साल, कहुआ	3.226	2.933	/163	
-''-	उतई	नीलगिरी, मिश्रित लट्ठा, जलाऊ	6.501	-	-	20
धमधा	व.प. कुम्हारी	सागौन लट्ठा, डेंगरी/कहुआ अन्य चिरान/मि.ज.	3.582	1.256	/22	1/2
बेमेतरा	बेमेतरा	सागौन लट्ठा	16.439	-	-	-
साजा	बेरला	सागौन लट्ठा/चिरान	0.076	0.312	-	-
		योग:-	315.411	4.501	2374/3199	26.5

टीपः-

(1) क्रेताओं को ई- ऑक्सन के पूर्व एम.एस.टी. सी. ई- कामर्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है.
(2) क्रेताओं को ई- ऑक्सन के पूर्व क्रय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है. सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई-एम.डी. की राशि जमा करना अनिवार्य है.
(3) लॉट की थप्पी सूची एवं फोटो एम.एस.टी.सी. ई- कार्मस पोर्टल में अपने आईडी से लॉगइन करके देख सकते हैं.
(4) ई- ऑक्सन में लॉट क्रय के पश्चात् प्रथम क्रेता को 40 सेकंड का समय प्राप्त होगा, उसी लॉट में अन्य क्रेताओं द्वारा 40 सेकंड के पूर्व क्रय करने पर 30 सेकंड का समय प्राप्त होगा.
(5) सफल क्रेताओं को अपना पूर्ण पता, मो.नं., पैन कार्ड एवं GST की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

फोन नं.- 75870-13100, ई-मेलः dfodurg@gmail.com

वनमण्डलाधिकारी
दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग (छ.ग.)

जी-242504304/5

भिलाई की सबसे बड़ी चुड़ी की दुकान
निखार बैंगल
मो.- 9826186026
Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

भारतीय बैग हाउस
फैंसी स्ट्राली, स्कूल बैग, ऑफिस बैग, सफर बैग, लेपटॉप बैग, फैंसी छतरी, रेनकोट इत्यादि के विक्रेता
VIP happy journey
AMERICAN TOURISTER
कृष्णा टाकीज रोड, बैंक ऑफ बडौदा के बाजू में रिसाली भिलाई, संजय गुप्ता: 93003-77572

भिलाई मसाला उद्योग
शुद्ध कुटे हुए मसाले,पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

राकेश ट्रेडर्स
विगत 6 वर्षो से यह दुकान पानी टंकी के सामने स्थानांतरित हो गई है।
Dealers
Marbles, Grinight, Black Stone, Nano & Double Charge Verified Tiles Digital Wall & Floor Tiles Cement Coloru etc.
रायपुर रेट पर माल उपलब्ध
Rakesh Sahu
9302443750, 9907127357
Krishna Talkies Road, Beside Hariom Furniture, Risali, Bhilai - 490006

मुख्यमंत्री साय ने किया साइबर भवन का उद्घाटन, बोले-

साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर अपराध की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी दक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें साइबर भवन का उद्घाटन एक अहम पहल है। मुख्यमंत्री साय ने अक्टूबर माह में प्रदेश में आयोजित 410 जनजागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से 23 लाख लोगों तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता अभियान साइबर अपराध रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री साय ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा हमारे पुलिस अधिकारियों ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों को ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के साथ हुए अनुबंध साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ द्वारा बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की प्रशंसा की।

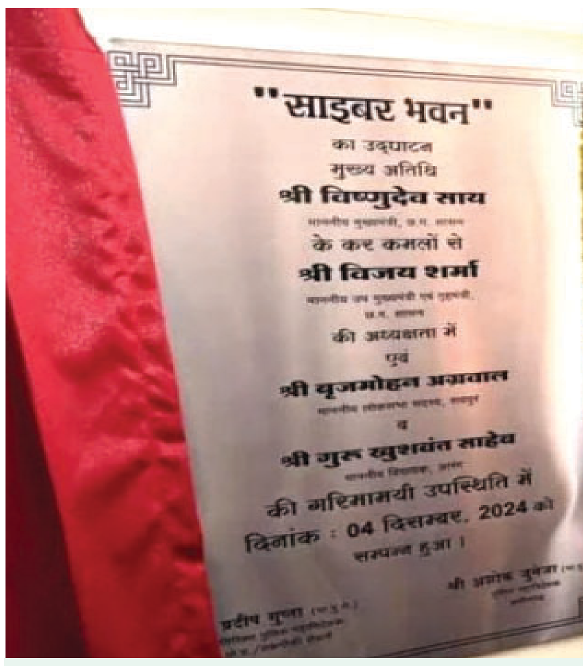

साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष पहल

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलवाद को सीमित करने में अद्भुत कार्य किया है। यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और रणनीतिक प्रयासों का परिणाम है। साइबर अपराधों पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष पहल की है। हाल ही में चलाए गए साइबर जागरूकता पखवाड़े का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज उद्घाटन किए गए साइबर भवन से बड़े अभियानों को संचालित किया जाएगा, जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन के अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और भी बड़े निर्णय लेकर जनता के हित में कार्य करेगी। इस अवसर पर विधायक गुरु खुशवंत साहेब, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, श्री एस आर पी कल्लूरी, विवेकानन्द सिन्हा, अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव गृह नेहा चम्पावत, हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

पुलिस कर्मियों के लिए 8 बैंकों से एमओयू

कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने साइबर अपराधों की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम नई तकनीक को अपनाकर साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में और अधिक दक्षता के साथ काम करेंगे। उन्होंने इस दिशा में काम कर रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और सुदर्शन की नीति को आधार बनाकर किए गए कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आज देश में सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरकार के रूप में उभर रही है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना ने 70 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है और समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस तंत्र को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे एक प्रभावी प्रणाली में तब्दील कर दिया।

नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ में खुला रेड कारपेट: मुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को नवा रायपुर में नीति आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संयुक्त रूप से ''छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के संबंध में हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम (स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप)'' में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए रेड कारपेट छत्तीसगढ़ में खुला है। निवेश की जटिलताएं अब छत्तीसगढ़ में नहीं रही। सिंगल विंडों सिस्टम ने सब कुछ बहुत सरल कर दिया है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां मिनरल्स का विपुल भंडार है, अनुकूल औद्योगिक वातावरण है, साथ ही उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा कर राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तैयार की गई है। इस नवीन नीति में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य

नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार संजीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ के नवीन औद्योगिक नीति की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। इस नीति से प्रदेश में सस्टेनेबल औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। नई नीति में एमएसएमई उद्योगों को सशक्त बनाने का अच्छा प्रयास किया गया है। नये क्षेत्रों में निवेश के लिए इंसेन्टिव स्कीम तैयार की गई है। इस उद्योग नीति में रोजगार सृजन महत्वपूर्ण पहलू है।

निवेश के लिए प्रदान किए गए 'इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में राज्य के 27 बड़े औद्योगिक समूहों को नवीन पूंजी निवेश के प्रस्ताव के संबंध में 32 हजार 225 करोड़ रुपए के निवेश के लिए इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर प्रदान किए। इनमें राज्य के कोर सेक्टर के साथ ही नये निवेश क्षेत्रों जैसे आईटी, एआई, डाटा सेंटर, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्प्रेस्ड बायो गैस जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। इनमें शिवालिक इंजीनियरिंग, मां दुर्गा आयरन एण्ड स्टील, एबीआरईएल ग्रीन एनर्जी, आरएजी फेरो एलायज, रिलायंस बायो एनर्जी, यश फेंस एण्ड एप्लायंसेस, शांति ग्रीन्स बायोफ्यूल, रेक बैंक डाटा सेंटर आदि सम्मिलित हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति में रोजगार सृजन, निर्यात प्रोत्साहन और उद्योगों की मंजूरी और स्थापना की प्रक्रिया के सरलीकरण पर फोकस किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने बताया कि नवीन औद्योगिक विकास नीति में राज्य की प्राथमिकताओं एवं राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिये प्रावधान किये गये हैं । कार्यक्रम में आयोजित पैनल डिस्कशन में रोजगारवर्धक औद्योगिक विकास में औद्योगिक अधोसंरचना, नीति समर्थन एवं उद्योग स्थापना हेतु औपचारिक आवश्यकताओं को कम करने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत का भी महत्वपूर्ण योगदान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है। इसके लिए हमें विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना होगा। विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। छत्तीसगढ़ के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा।

उद्योगपतियों से सुझावों को किया गया शामिल

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेकर किया गया है। नई नीति तैयार करने में उद्योगपतियों से सुझावों को शामिल किया गया है। इस नीति से प्रदेश में निवेश तो आएगा ही, नये उद्योगों की स्थापना होगी, साथ ही राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा।

नक्सल उन्मूलन पर सीएम साय ने ली समीक्षा बैठक, कहा-

बीते 11 माह में नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकार ने लड़ी निर्णायक लड़ाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें उसी दिशा में प्रभावी रणनीतियां तैयार करनी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल आत्मसमर्पण के लिए जनजागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। बस्तर क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसकी झलक हाल ही में संपन्न बस्तर ओलंपिक में भी दिखी।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15,000 मकानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद मुक्त होगा। सरकार की प्राथमिकता स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने और विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करने की है।

बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सिविल सोसाइटी को अभियान से जोड़ने और नक्सलियों के आत्मसमर्पण हेतु किए जा रहे प्रयासों को तेज करने पर बल दिया। श्री शर्मा ने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएगे।

बैठक में सुरक्षा ग्रिड का विस्तार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए कैंप स्थापित करना, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और आवास संबंधी योजनाएं और ज्वाइंट एक्शन प्लान सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, एसआरपी कल्लूरी, विवेकानन्द सिन्हा, अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव गृह नेहा चम्पावत हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

निकायों में 15 हजार नए आवास स्वीकृत, सीएम साय बोले-

देश में हर गरीब के पक्के मकान का सपना होगा साकार

राज्य के सभी शहर शामिल, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन के आधार पर मिली नए आवासों की स्वीकृति

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत तेजी से पूर्ण किए आवासों और योजना में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 15 हजार नए आवासों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शहरों के लिए 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्दी ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की कोशिशों से राज्य के सभी शहरों के लिए ये आवास स्वीकृत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत दी मंजूरी

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत 15 हजार नवीन आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति के साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन का भी उल्लेख है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास स्वीकृत करते हुए मंत्रालय ने इसकी सूची भी भेजी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य शासन को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करते हुए विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।

'सबके लिए आवास' मिशन के तहत योजना का क्रियान्वयन

भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास' मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।

ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को मिले योजना का लाभ

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नए आवासों की स्वीकृति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर पात्र परिवार को आवास दिलाने प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री साव ने वर्तमान में चल रहे हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए संबंधित परिवारों को पर्याप्त समय देने के साथ ही नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950